bjpkamaljyoti@gmail.com संवत 2078 युगाब्द 5123

कुल पृष्ठ – 34 अंक – 12

वर्तमान

कमल ज्योति

सुराज अंक

मूल्य : ₹10

बहू-बेटी की सुरक्षा और अधिकार
गरीबों के पक्के मकान का सपना साकार
सोच ईमानदार काम दमदार
बिना भेदभाव भर्ती रोज़गार
मुफ्त राशन गरीब के द्वार
यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार
सोच ईमानदार काम दमदार
यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार

यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार

चिर विजय की साधना...

सोच ईमानदार, काम असरदार
यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार
यूपी फिर मांगे
भाजपा सरकार
कमल का बटन दबाएं

वर्तमान
कमल ज्योति

संरक्षक
श्री स्वतंत्र देव सिंह
सम्पादक
अरुण कान्त त्रिपाठी
प्रबन्ध सम्पादक
राजकुमार
प्रकाशक
प्रो0 श्याम नन्दन सिंह
पृष्ठ संयोजक
ओम प्रकाश पंडित

कार्यालय

कमल ज्योति, 7–विधानसभा मार्ग
लखनऊ – 1
फोन :– 0522–2200187
फैक्स :– 0522–2612437

Email- bjpkamaljyoti@gmail.com

पत्रिका में प्रकाशित आलेखों से सम्पादकीय सहमति अनिवार्य नहीं

मुद्रक

नूतन ऑफसेट मुद्रण केन्द्र, राजेन्द्र नगर, लखनऊ–4

जय हिन्द!

संपादकीय

सुराज में अन्त्योदय

सुराज का अर्थ केवल राजनीतिक स्तर पर विदेशी शासन से स्वाधीनता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि सुंदर राजव्यवस्था जिसमें प्रजा के सुख ,शांति संवृद्धि है इसमें सांस्कृतिक व नैतिक स्वाधीनता का विचार भी निहित है। यह नया भारत बनाने में परस्पर सहयोग समन्वय व मेल–मिलाप पर बल देता है। शासन के स्तर पर यह 'सच्चे लोकतंत्र का पर्याय' है। गाँधी जी का स्वराज 'आमजन का राज' है, जो दीन–दुखियों का उद्धार अर्थात "सर्वोदय" सर्व–कल्याण का समर्थन का प्रयास था । इस लोक–कल्याण में राजसत्ता का योगदान ही जिनकी प्राथमिकता रहती है।

आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष, 73वॉ गणतंत्र दिवस मना रहा देश आज एक सशक्त, सुरक्षित ,स्वाभिमानी,आत्मनिर्भर भारत के रुप मे दुनिया मे खड़ा है।

देश प्रदेश में आधुनिक एक्सप्रेस–वे, बिजली, पानी की उचित व्यवस्था, स्वच्छता, शिक्षा, चिकित्सा, गरीबो को आवास, गैस, शौचालय, संकट काल मे मुफ्त में राशन हमारी सुराज की पहचान बनते जा रहे है।

मोदी योगी जी की डबल इंजन की सरकार यानी लोककल्याण में आपसी समन्वय, सहकार से अंत्योदय का लक्ष्य पूरा हो रहा है।

लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय के द्वारा एकात्म मानववाद की संकल्पना को साकार करते यह सरकारें जन, जल, जमीन, जंगल, जानवर, प्रकृति की सुरक्षा संरक्षण करते हुए आम लोगों के जीवन को सुखमय बना रही है। आज नदियां कल–कल, छल–छल करते प्रवाह मान हो पवित्र जल से परिपूर्ण हो रही है। तो दूसरी तरफ खेती–किसानी, बागवानी, उद्योग–धंधे सब निरंतर भारत को एक सशक्त राष्ट्र के रूप में खड़ा कर रहे हैं। एक भारत, श्रेष्ठ भारत का नारा आज चहुंओर दिखाई दे रहा है। आज उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, नैतिक, सामाजिक, आत्म निर्भर प्रदेश के रूप में खड़ा है।

उत्तर प्रदेश कृषि की नई नई तकनीक के प्रयास से किसानों की आय निरंतर बढ़ती जा रही है हमारे संविधान की प्रस्तावना में ही लोकतंत्र, न्याय स्वतंत्रता, समानता और बन्धुत्व के मार्ग दर्शक सिद्धान्त हैं। जिसके कारण हमारा लोकतंत्र मजबूती से खड़ा है। भारतीय जीवन मूल्य, मूल अधिकार तथा नागरिकों के मूल कर्तव्यों के रूप में हमारा संविधान सुराज का प्रतीक है। आज कोविड ''वैश्विक'' महामारी में भी जनता के सहयोग से सरकारों ने सफल टीकाकरण कर महामारी पर विजय पायी। आज हम कह सकते हैं कि भारत में आमजन के सहयोग विश्वास से देश नित नई ऊंचाइयों को रोज छू रहा है उसमें आमजन के अधिकारों के साथ–साथ कर्तव्य पथ पर निरंतर चलने से यह ऊंचाई देश प्रदेश को मिल रही है लोकतंत्र में लोक कल्याण, लोकसंवाद, लोकव्यवस्था, लोकव्यवहार, लोककल्याण व्यावहारिक रूप से प्रगति के कारक बनते हैं।

आज वर्तमान में चार प्रदेशों सहित उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव चल रहा है जिसमे हमारा कर्तव्य बनता है कि एक लोक कल्याणकारी शासन व्यवस्था के लिए अपने मत का प्रयोग अवश्य करें, और सुराज की संकल्पना को साकार करें।▪

akatri.t@gmail.com

गतिशील लोकतंत्र, राष्ट्रीय एकता का उत्सव

प्यारे देशवासियो!
नमस्कार!

तिहत्तरवें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर, देश और विदेश में रहने वाले आप सभी भारत के लोगों को मेरी हार्दिक बधाई! हम सबको एक सूत्र में बांधने वाली भारतीयता के गौरव का यह उत्सव है। सन 1950 में आज ही के दिन हम सब की इस गौरवशाली पहचान को औपचारिक स्वरूप प्राप्त हुआ था। उस दिन, भारत विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र के रूप में स्थापित हुआ और हम, भारत के लोगों ने एक ऐसा संविधान लागू किया जो हमारी सामूहिक चेतना का जीवंत दस्तावेज है। हमारे विविधतापूर्ण और सफल लोकतंत्र की सराहना पूरी दुनिया में की जाती है। हर साल गणतंत्र दिवस के दिन हम अपने गतिशील लोकतन्त्र तथा राष्ट्रीय एकता की भावना का उत्सव मनाते हैं। महामारी के कारण इस वर्ष के उत्सव में धूम–धाम भले ही कुछ कम हो परंतु हमारी भावना हमेशा की तरह सशक्त है।

मा0 राष्ट्रपति जी का संदेश

गणतन्त्र दिवस का यह दिन उन महानायकों को याद करने का अवसर भी है जिन्होंने स्वराज के सपने को साकार करने के लिए अतुलनीय साहस का परिचय दिया तथा उसके लिए देशवासियों में संघर्ष करने का उत्साह जगाया। दो दिन पहले, 23 जनवरी को हम सभी देशवासियों ने 'जय–हिन्द' का उद्घोष करने वाले नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की 125वीं जयंती पर उनका पुण्य स्मरण किया है। स्वाधीनता के लिए उनकी ललक और भारत को गौरवशाली बनाने की उनकी महत्वाकांक्षा हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है।

हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे संविधान का निर्माण करने वाली सभा में उस दौर की सर्वश्रेष्ठ विभूतियों का प्रतिनिधित्व था। वे लोग हमारे महान स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख ध्वज–वाहक थे। लंबे अंतराल के बाद, भारत की राष्ट्रीय चेतना का पुनर्जागरण हो रहा था। इस प्रकार, वे असाधारण महिलाएं और पुरुष एक नई जागृति के अग्रदूत की भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने संविधान के प्रारूप के प्रत्येक अनुच्छेद, वाक्य और शब्द पर, सामान्य जन–मानस के हित में, विस्तृत चर्चा की। वह विचार–मंथन लगभग तीन वर्ष तक चला। अंततः, डॉक्टर बाबासाहब आम्बेडकर ने प्रारूप समिति के अध्यक्ष की हैसियत से, संविधान को आधिकारिक स्वरूप प्रदान किया। और वह हमारा आधारभूत ग्रंथ बन गया।

यद्यपि हमारे संविधान का कलेवर विस्तृत है क्योंकि उसमें, राज्य के काम–काज की व्यवस्था का भी विवरण है। लेकिन संविधान की संक्षिप्त प्रस्तावना में लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मार्गदर्शक सिद्धांत, सार–गर्भित रूप से उल्लिखित हैं। इन आदर्शों से उस ठोस आधारशिला का निर्माण हुआ है जिस पर हमारा भव्य गणतंत्र मजबूती से खड़ा है। इन्हीं जीवन–मूल्यों में हमारी सामूहिक विरासत भी परिलक्षित होती है।

इन जीवन–मूल्यों को, मूल अधिकारों तथा नागरिकों के मूल कर्तव्यों के रूप में हमारे संविधान द्वारा बुनियादी महत्व प्रदान किया गया है। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्यों का नागरिकों द्वारा पालन करने से मूल अधिकारों के लिए समुचित वातावरण बनता है। आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करने के मूल कर्तव्य को निभाते हुए हमारे करोड़ों देशवासियों ने स्वच्छता अभियान से लेकर कोविड

टीकाकरण अभियान को जन–आंदोलन का रूप दिया है। ऐसे अभियानों की सफलता का बहुत बड़ा श्रेय हमारे कर्तव्य–परायण नागरिकों को जाता है। मुझे विश्वास है कि हमारे देशवासी इसी कर्तव्य–निष्ठा के साथ राष्ट्र हित के अभियानों को अपनी सक्रिय भागीदारी से मजबूत बनाते रहेंगे।

प्यारे देशवासियो,

भारत का संविधान 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। उस दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके दो महीने बाद 26 जनवरी, 1950 से हमारा संविधान पूर्णतः प्रभावी हुआ। ऐसा सन 1930 के उस दिन को यादगार बनाने के लिए किया गया था जिस दिन भारतवासियों ने पूरी आजादी हासिल करने का संकल्प लिया था। सन 1930 से 1947 तक, हर साल 26 जनवरी को 'पूर्ण स्वराज दिवस' के रूप में मनाया जाता था, अतः यह तय किया गया कि उसी दिन से संविधान को पूर्णतः प्रभावी बनाया जाए।

सन 1930 में महात्मा गांधी ने देशवासियों को 'पूर्ण स्वराज दिवस' मनाने का तरीका समझाया था। उन्होंने कहा था : चूंकि हम अपने ध्येय को अहिंसात्मक और सच्चे उपायों से ही प्राप्त करना चाहते हैं, और यह काम हम केवल आत्म–शुद्धि के द्वारा ही कर सकते हैं, इसलिए हमें चाहिए कि उस दिन हम अपना सारा समय यथाशक्ति कोई रचनात्मक कार्य करने में बिताएं।"

यथाशक्ति रचनात्मक कार्य करने का गांधीजी का यह उपदेश सदैव प्रासंगिक रहेगा। उनकी इच्छा के अनुसार गणतंत्र दिवस का उत्सव मनाने के दिन और उसके बाद भी, हम सब की सोच और कार्यों में रचनात्मकता होनी चाहिए। गांधीजी चाहते थे कि हम अपने भीतर झांक कर देखें, आत्म–निरीक्षण करें और बेहतर इंसान बनने का प्रयास करें, और उसके बाद बाहर भी देखें, लोगों के साथ सहयोग करें और एक बेहतर भारत तथा बेहतर विश्व के निर्माण में अपना योगदान करें।

प्यारे देशवासियो,

मानव–समुदाय को एक–दूसरे की सहायता की इतनी जरूरत कभी नहीं पड़ी थी जितनी कि आज है। अब दो साल से भी अधिक समय बीत गया है लेकिन मानवता का कोरोना–वायरस के विरुद्ध संघर्ष अभी भी जारी है। इस महामारी में हजारों लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा है। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर आघात हुआ है। विश्व समुदाय को अभूतपूर्व विपदा का सामना करना पड़ा है। नित नए रूपों में यह वायरस नए संकट प्रस्तुत करता रहा है। यह स्थिति, मानव जाति के लिए एक असाधारण चुनौती बनी हुई है।

महामारी का सामना करना भारत में अपेक्षाकृत अधिक कठिन होना ही था। हमारे देश में जनसंख्या का घनत्व बहुत ज्यादा है, और विकासशील अर्थव्यवस्था होने के नाते हमारे पास इस अदृश्य शत्रु से लड़ने के लिए उपयुक्त स्तर पर बुनियादी ढांचा तथा आवश्यक संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं थे। लेकिन ऐसे कठिन समय में ही किसी राष्ट्र की संघर्ष करने की क्षमता निखरती है। मुझे यह कहते हुए गर्व का अनुभव होता है कि हमने कोरोना–वायरस के खिलाफ असाधारण दृढ़–संकल्प और कार्य–क्षमता का प्रदर्शन किया है। पहले वर्ष के दौरान ही, हमने स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को विस्तृत तथा मजबूत बनाया और दूसरे देशों की मदद के लिए भी आगे बढ़े। दूसरे वर्ष तक, हमने स्वदेशी टीके विकसित कर लिए और विश्व इतिहास में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया। यह अभियान तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हमने अनेक देशों को वैक्सीन तथा चिकित्सा संबंधी अन्य सुविधाएं प्रदान कराई हैं। भारत के इस योगदान की वैश्विक संगठनों ने सराहना की है।

दुर्भाग्य से, संकट की स्थितियां आती रही हैं, क्योंकि वायरस, अपने बदलते स्वरूपों में वापसी करता रहा है। अनगिनत परिवार, भयानक विपदा के दौर से गुजरे हैं। हमारी सामूहिक पीड़ा को व्यक्त करने के लिए मेरे पास

शब्द नहीं हैं। लेकिन एकमात्र सांत्वना इस बात की है कि बहुत से लोगों की जान बचाई जा सकी है। महामारी का प्रभाव अभी भी व्यापक स्तर पर बना हुआ है, अतः हमें सतर्क रहना चाहिए और अपने बचाव में तनिक भी ढील नहीं देनी चाहिए। हमने अब तक जो सावधानियां बरती हैं, उन्हें जारी रखना है। मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना कोविड–अनुरूप व्यवहार के अनिवार्य अंग रहे हैं। कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों द्वारा बताई गई सावधानियों का पालन करना आज हर देशवासी का राष्ट्र–धर्म बन गया है। यह राष्ट्र–धर्म हमें तब तक निभाना ही है, जब तक यह संकट दूर नहीं हो जाता।

संकट की इस घड़ी में हमने यह देखा है कि कैसे हम सभी देशवासी एक परिवार की तरह आपस में जुड़े हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के कठिन दौर में हम सबने एक–दूसरे के साथ निकटता का अनुभव किया है। हमने महसूस किया है कि हम एक–दूसरे पर कितना निर्भर करते हैं। कठिन परिस्थितियों में लंबे समय तक काम करके, यहां तक कि मरीजों की देखभाल के लिए अपनी जान जोखिम में डाल कर भी डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिक्स ने मानवता की सेवा की है। बहुत से लोगों ने देश में गतिविधियों को सुचारु रूप से जारी रखने के लिए यह सुनिश्चित किया है कि अनिवार्य सुविधाएं उपलब्ध रहें तथा सप्लाई–चेन में रुकावट न पैदा हो। केंद्र और राज्य स्तर पर जन–सेवकों, नीति–निर्माताओं, प्रशासकों और अन्य लोगों ने समयानुसार कदम उठाए हैं।

इन प्रयासों के बल पर हमारी अर्थ–व्यवस्था ने फिर से गति पकड़ ली है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भारत की दृढ़ता का यह प्रमाण है कि पिछले साल आर्थिक विकास में आई कमी के बाद इस वित्त वर्ष में अर्थ–व्यवस्था के प्रभावशाली दर से बढ़ने का अनुमान है। यह पिछले वर्ष शुरू किए गए आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता को भी दर्शाता है। सभी आर्थिक क्षेत्रों में सुधार लाने और आवश्यकता–अनुसार सहायता प्रदान करने हेतु सरकार निरंतर सक्रिय रही है। इस प्रभावशाली आर्थिक प्रदर्शन के पीछे कृषि और मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्रों में हो रहे बदलावों का प्रमुख योगदान है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि हमारे किसान, विशेषकर छोटी जोत वाले युवा किसान प्राकृतिक खेती को उत्साह–पूर्वक अपना रहे हैं।

लोगों को रोजगार देने तथा अर्थ–व्यवस्था को गति प्रदान करने में छोटे और मझोले उद्यमों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे इनोवेटिव युवा उद्यमियों ने स्टार्ट–अप ईको–सिस्टम का प्रभावी उपयोग करते हुए सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। हमारे देश में विकसित, विशाल और सुरक्षित डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म की सफलता का एक उदाहरण यह है कि हर महीने करोड़ों की संख्या में डिजिटल ट्रांज़ेक्शन किए जा रहे हैं।

जन–संसाधन से लाभ उठाने यानि डेमोग्राफिक डिविडेंड प्राप्त करने के लिए, हमारे पारंपरिक जीवन–मूल्यों एवं आधुनिक कौशल के आदर्श संगम से युक्त राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिये सरकार ने समुचित वातावरण उपलब्ध कराया है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि विश्व में सबसे ऊपर की 50 'इनोवेटिव इकॉनोमीज़' में भारत अपना स्थान बना चुका है। यह उपलब्धि और भी संतोषजनक है कि हम व्यापक समावेश पर जोर देने के साथ–साथ योग्यता को बढ़ावा देने में सक्षम हैं।

देवियो और सज्जनो,

पिछले वर्ष ओलंपिक खेलों में हमारे खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन से लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। उन युवा विजेताओं का आत्मविश्वास आज लाखों देशवासियों को प्रेरित कर रहा है।

हाल के महीनों में, हमारे देशवासियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिबद्धता और कर्मठता से राष्ट्र और समाज को मजबूती प्रदान करने वाले अनेक उल्लेखनीय उदाहरण मुझे देखने को मिले हैं। उनमें से मैं केवल दो उदाहरणों का उल्लेख करूंगा। भारतीय नौसेना और कोचीन

शिपयार्ड लिमिटेड की समर्पित टीमों ने स्वदेशी व अति–आधुनिक विमानवाहक पोत 'आई.ए.सी.–विक्रांत' का निर्माण किया है जिसे हमारी नौसेना में शामिल किया जाना है। ऐसी आधुनिक सैन्य क्षमताओं के बल पर, अब भारत की गणना विश्व के प्रमुख नौसेना–शक्ति–सम्पन्न देशों में की जाती है। यह रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होने का एक प्रभावशाली उदाहरण है। इससे हटकर एक विशेष अनुभव मुझे बहुत हृदय–स्पर्शी लगा। हरियाणा के भिवानी जिले के सुई नामक गांव में उस गांव से निकले कुछ प्रबुद्ध नागरिकों ने संवेदनशीलता और कर्मठता का परिचय देते हुए 'स्व–प्रेरित आदर्श ग्राम योजना' के तहत अपने गांव का कायाकल्प कर दिया है। अपने गांव यानि अपनी मातृभूमि के प्रति लगाव और कृतज्ञता का यह एक अनुकरणीय उदाहरण है। कृतज्ञ लोगों के हृदय में अपनी जन्मभूमि के प्रति आजीवन ममता और श्रद्धा बनी रहती है।

ऐसे उदाहरण से मेरा यह विश्वास दृढ़ होता है कि एक नया भारत उभर रहा है – सशक्त भारत और संवेदनशील भारत। मुझे विश्वास है कि इस उदाहरण से प्रेरणा लेकर अन्य सक्षम देशवासी भी अपने–अपने गांव एवं नगर के विकास के लिए योगदान देंगे।

इस संदर्भ में आप सभी देशवासियों के साथ मैं एक निजी अनुभव साझा करना चाहूंगा। मुझे पिछले वर्ष जून के महीने में कानपुर देहात जिले में स्थित अपनी जन्म–भूमि अर्थात अपने गांव परौंख जाने का सौभाग्य मिला था। वहां पहुंचकर, अपने आप ही, मुझमें अपने गांव की माटी को माथे पर लगाने की भावना जाग उठी क्योंकि मेरी मान्यता है कि अपने गांव की धरती के आशीर्वाद के बल पर ही मैं राष्ट्रपति भवन तक पहुंच सका हूं। मैं विश्व में जहां भी जाता हूं, मेरा गांव और मेरा भारत मेरे हृदय में विद्यमान रहते हैं। भारत के जो लोग अपने परिश्रम और प्रतिभा से जीवन की दौड़ में आगे निकल सके हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि अपनी जड़ों को, अपने गांव–कस्बे–शहर को और अपनी माटी को हमेशा याद रखिए। साथ ही, आप सब अपने जन्म–स्थान और देश की जो भी सेवा कर सकते हैं, अवश्य कीजिए। भारत के सभी सफल व्यक्ति यदि अपने–अपने जन्म–स्थान के विकास के लिए निष्ठापूर्वक कार्य करें तो स्थानीय–विकास के आधार पर पूरा देश विकसित हो जाएगा।

प्यारे देशवासियो,

आज, हमारे सैनिक और सुरक्षाकर्मी देशाभिमान की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। हिमालय की असहनीय ठंड में और रेगिस्तान की भीषण गर्मी में अपने परिवार से दूर वे मातृभूमि की रक्षा में तत्पर रहते हैं। हमारे सशस्त्र बल तथा पुलिसकर्मी देश की सीमाओं की रक्षा करने तथा आंतरिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए रात–दिन चौकसी रखते हैं ताकि अन्य सभी देशवासी चैन की नींद सो सकें। जब कभी किसी वीर सैनिक का निधन होता है तो सारा देश शोक–संतप्त हो जाता है। पिछले महीने एक दुर्घटना में देश के सबसे बहादुर कमांडरों में से एक दृ जनरल बिपिन रावत दृ उनकी धर्मपत्नी तथा अनेक वीर योद्धाओं को हमने खो दिया। इस हादसे से सभी देशवासियों को गहरा दुख पहुंचा।

देवियो और सज्जनो,

देशप्रेम की भावना देशवासियों की कर्तव्य–निष्ठा को और मजबूत बनाती है। चाहे आप डॉक्टर हों या वकील, दुकानदार हों या ऑफिस–वर्कर, सफाई कर्मचारी हों या मजदूर, अपने कर्तव्य का निर्वहन निष्ठा व कुशलता से करना देश के लिए आपका प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण योगदान है।

सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के रूप में, मुझे यह उल्लेख करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि यह वर्ष सशस्त्र बलों में महिला सशक्तीकरण की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण रहा है। हमारी बेटियों ने परंपरागत सीमाओं को पार किया है, और अब नए क्षेत्रों में महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन की सुविधा आरंभ हो गई है। साथ ही, सैनिक स्कूलों तथा सुप्रतिष्ठित नेशनल डिफेंस एकेडमी से महिलाओं के आने का मार्ग प्रशस्त होने से सेनाओं की टैलेंट–पाइपलाइन तो समृद्ध होगी ही, हमारे सशस्त्र बलों को बेहतर जेन्डर बैलेंस का लाभ भी मिलेगा।

मुझे विश्वास है कि भविष्य की चुनौतियों का सामना करने

के लिए भारत आज बेहतर स्थिति में है। इक्कीसवीं सदी को जलवायु परिवर्तन के युग के रूप में देखा जा रहा है और भारत ने अक्षय ऊर्जा के लिए अपने साहसिक और महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के साथ विश्व–मंच पर नेतृत्व की स्थिति बनाई है। निजी स्तर पर, हम में से प्रत्येक व्यक्ति गांधीजी की सलाह के अनुरूप अपने आसपास के परिवेश को सुधारने में अपना योगदान कर सकता है। भारत ने सदैव समस्त विश्व को एक परिवार ही समझा है। मुझे विश्वास है कि विश्व बंधुत्व की इसी भावना के साथ हमारा देश और समस्त विश्व समुदाय और भी अधिक समरस तथा समृद्ध भविष्य की ओर आगे बढ़ेंगे।

प्यारे देशवासियो,

इस वर्ष जब हमारे देश की आजादी के 75 साल पूरे होंगे तब हम अपने राष्ट्रीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव पार करेंगे। इस अवसर को हम 'आजादी का अमृत महोत्सव' के रूप में मना रहे हैं। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि बड़े पैमाने पर हमारे देशवासी, विशेषकर हमारे युवा, इस ऐतिहासिक आयोजन में उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। यह न केवल अगली पीढ़ी के लिए, बल्कि हम सभी के लिए अपने अतीत के साथ पुनः जुड़ने का एक शानदार अवसर है। हमारा स्वतंत्रता संग्राम हमारी गौरवशाली ऐतिहासिक यात्रा का एक प्रेरक अध्याय था। स्वाधीनता का यह पचहत्तरवां वर्ष उन जीवन–मूल्यों को पुनः जागृत करने का समय है जिनसे हमारे महान राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरणा मिली थी। हमारी स्वाधीनता के लिए अनेक वीरांगनाओं और सपूतों ने अपने प्राण न्योछावर किए हैं। स्वाधीनता दिवस तथा गणतन्त्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व न जाने कितनी कठोर यातनाओं एवं बलिदानों के पश्चात नसीब हुए हैं। आइए! गणतन्त्र दिवस के अवसर पर हम सब श्रद्धापूर्वक उन अमर बलिदानियों का भी स्मरण करें।

प्यारे देशवासियो,

हमारी सभ्यता प्राचीन है परन्तु हमारा यह गणतंत्र नवीन है। राष्ट्र निर्माण हमारे लिए निरंतर चलने वाला एक अभियान है। जैसा एक परिवार में होता है, वैसे ही एक राष्ट्र में भी होता है कि एक पीढ़ी अगली पीढ़ी का बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करती है। जब हमने आज़ादी हासिल की थी, उस समय तक औपनिवेशिक शासन के शोषण ने हमें घोर गरीबी की स्थिति में डाल दिया था। लेकिन उसके बाद के पचहत्तर वर्षों में हमने प्रभावशाली प्रगति की है। अब युवा पीढ़ी के स्वागत में अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। हमारे युवाओं ने इन अवसरों का लाभ उठाते हुए सफलता के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। मुझे विश्वास है कि इसी ऊर्जा, आत्म–विश्वास और उद्यमशीलता के साथ हमारा देश प्रगति पथ पर आगे बढ़ता रहेगा तथा अपनी क्षमताओं के अनुरूप, विश्व समुदाय में अपना अग्रणी स्थान अवश्य प्राप्त करेगा।

मैं आप सभी को पुनः गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।

धन्यवाद, जय हिन्द! ■.

सुराज में बेटियां : मोदी

'हमारी बेटियां भी अब देश रक्षा में योगदान दे रही हैं। NDA में बेटियों का एडमिशन हो रहा है। 2019 के चुनावों में हमने देखा पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने योगदान दिया। आज देश में महिलाएं अहम मंत्रालय संभाल रही हैं। यह बदलाव समाज खुद कर रहा है। यह बदलाव साफ संकेत है कि नया भारत कैसा होगा? कितना सामर्थ्यशाली होगा?

आज किसानों को आत्मनिर्भर बनाने नेचुरल फार्मिंग पर जोर दिया जा रहा है। गुणवत्ता युक्त आहार के लिए गुणवत्तायुक्त उत्पादन भी जरूरी है। नेचुरल फार्मिंग के लिए ब्रह्माकुमारी जैसे संस्थान बड़ा योगदान कर सकते हैं। दुनिया को क्लीन एनर्जी में भारत से बहुत अपेक्षाएं हैं। जनजागरण के लिए बड़े अभियान की जरूरत है।'

अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज करोड़ों देशवासी स्वर्णिम भारत की नींव रख रहे हैं। हमारी निजी और राष्ट्रीय सफलताएं अलग नहीं हैं। राष्ट्र की प्रगति में ही हमारी प्रगति है। राष्ट्र के अस्तित्व में हमारा अस्तित्व है, यही भाव एक ताकत बन रहा है। आज देश जो कुछ कर रहा है, उसमें सबके प्रयास शामिल है, सबका साथ सबका विश्वास और सबका प्रयास देश का मूल मंत्र बन रहा है। हम ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं, जिसमें भेदभाव की जगह न हो। ऐसा समाज बना रहे हैं, जो सामाजिक न्याय की बुनियाद पर मजबूती से खड़ा है।

भारत अपना मूल स्वभाव को नहीं बदलता

प्रधानमंत्री ने कहा, 'हम ऐसा भारत बना रहे हैं, जो प्रगतिशील है। भारत की सबसे बड़ी ताकत यह है कि कैसा भी समय आए, कितना भी अंधेरा छाए भारत अपने मूल स्वभाव को बनाए रखता है। हमारे युगों युगों का इतिहास है, जब दुनिया महिलाओं को लेकर पुरानी सोच में जकड़ी थी, तब भारत मातृ शक्ति की पूजा देवी के रूप में करता था। हमारे गार्गी, जैसी विदूषी ज्ञान देती थीं।'

'हमें ऐसा भारत बनाना है, जिसकी जड़ें परंपरा से जुड़ी होंगी, हमें अपने सभ्यता, संस्कारों को जीवंत रखना हैं। हमें अपनी विरासत को संभाल कर रखना है। इसके साथ ही तकनीक सहित हर क्षेत्र में देश को आधुनिक भी बनाना है।'

इस अमृत महोत्सव में भी भविष्य की तरफ ध्यान रखना है।

मोदी जी ने कहा, 'आने वाले 25 साल घोर परिश्रम वाले हैं। हमने गुलामी में जो गंवाया है, उसे पाने के 25 साल हैं। इस अमृत महोत्सव में भी भविष्य की तरफ ध्यान रखना है। कालखंड के साथ देश, व्यक्ति और समाज में बुराइयां प्रवेश कर जाती हैं। हमारे समाज में बदलते युग के साथ ढालने की अलग ही शक्ति है।'

प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि हमारे समाज की सबसे बड़ी ताकत यह है कि समय–समय पर समाज से ही सुधारने वाले आते हैं और वे समाज सुधारक बुराइयों पर प्रहार करते हैं। ऐसे समाज सुधारकों को कई बार तिरस्कार और विरोध का भी सामना करना होता है। ऐसे सुधारक डिगते नहीं है और धीरे–धीरे समाज उन्हें स्वीकार करता हैं। हर काल खंड में समाज को दोष मुक्त रखना निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा हो।

75 साल में केवल अधिकारों की बात हुई, कर्तव्य भूल गए

बीते 75 साल में देश में सबसे बड़ी बुराई आई, वो थी कर्तव्यों को भूलकर केवल अधिकारों की बात करना। बीते 75 साल में हम अधिकारों के लिए लड़ते रहे, समय खपाते रहे, लेकिन कर्तव्यों को भूल गए। कर्तव्य भूलकर केवल अधिकारों की बात करने से नुकसान हुआ है। 75 साल में कर्तव्यों को दूर करने से कमियां और नुकसान हुए है, इसकी भरपाई आने वाले 25 साल में कर्तव्य की साधना करके पूरी कर सकते हैं।

देश के नागरिकों में कर्तव्यबोध जागृत करने की जरूरत है। एक कमरे में अंधेरा दूर करने के लिए कई लोग जुगत लगा रहे थे। एक समझदार ने दीया जला दिया। हमें उसी तरह हमें एक दीया जलाना है, कर्तव्य का दीया जलाना है। इससे समाज में व्याप्त बुराइयां भी दूर होंगी। भारत भूमि को प्यार करनेवाला कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो देश को नई ऊंचाइयों पर न ले जाना चाहता होगा। इसके लिए हमें कर्तव्य योगियों पर बल देना ही होगा।

भारत को बदनाम करने का अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहा

मोदी ने कहा, देश को बदनाम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर षड्यंत्र चल रहा है। आज आजादी के अमृत महोत्सव पर यह भी जरूरी है कि दुनिया के देशों में भारत के बारे में सही बात जाए। वैश्विक संस्थाएं भारत के बारे में सही जानकारी दें। ब्रह्माकुमारी जैसी संस्थाएं यह काम कर सकती हैं। ब्रह्माकुमारी जैसी संस्थाएं अपनी बाहर की ब्रांचों से हर साल कम से कम 500 विदेशी लोगों को भारत की यात्रा पर लाएं। इससे वे लोग बाहर जाकर हमारे देश के बारे में बताएंगे और एक सही छवि बनेगी।

इस कार्यक्रम के जरिए 15 हजार प्रोग्राम के जरिए 10 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य है। कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला, प्रदेश के राज्यपाल कलराज मिश्र, CM अशोक गहलोत, केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल, राजस्थान के तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग भी जुड़े।

ब्रह्माकुमारी संस्थान के कार्यकारी सचिव बी.के मृत्युंजय ने बताया कि संस्थान की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतनमोहिनी की अध्यक्षता में आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन एवं अभियान में देश ही नहीं बल्कि विदेश से हस्तियां भी शामिल हुईं। ब्रह्माकुमारी संस्थान की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बी.के मोहिनी न्यूयार्क से उपस्थित रहीं। इस अवसर पर ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित एक्टर रिक्की केज की ओर से एक वीडियो एलबम भी रिलीज किया गया।▪

अभियानों का आगाज

1. वैक्सीनेशन अभियानः गांव–गांव में लोगों के लिए वैक्सीन लगाने और जागरूक करने।
2. आत्मनिर्भर किसानः किसानों को यौगिक–जैविक खेती के प्रति जागरूक करने।
3. महिलाएंः नए भारत की ध्वज वाहक अभियान4. अनदेखा भारत साइकिल रैली
4. सड़क सुरक्षा के लिए देशभर में 150 बाइक रैली– एक बाइक रैली में 75 बाइक शामिल होंगी। सभी रैलियों को मिलाकर 25 हजार किमी की दूरी तय की जाएगी।
5. आबू रोड से दिल्ली जाने वाली 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' बाइक रैली।
6. युवाओं को सशक्त बनाने के लिए 'बस यात्रा' और 'स्वच्छ भारत अभियान।'

सुराज की पहल
'हमने विकास सबका किया, तुष्टिकरण किसी का नही! - आदित्यनाथ'

मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह, उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य तथा केन्द्रीय मंत्री एवं प्रदेश के सह चुनाव प्रभारी श्री अनुराग ठाकुर ने भाजपा का झंडा दिखाकर चुनाव प्रचार के लिए एलईडी रथों को रवाना किया। पार्टी सभी 403 विधानसभाओं में चुनाव वैन के जरिये चुनाव प्रचार का शुभारंभ किया है।

श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार ने जो कहा, उसे पूरा किया। भाजपा सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से प्रदेश की जनता का विकास कर रही है। 25 करोड़ जनता ने देखा कि 2017 से पहले व्यापारी और संभ्रांत नागरिक पलायन करते थे, इससे प्रदेश की प्रगति अवरुद्ध हो गयी थी। 2017 के बाद अपराधी पलायन कर रहे हैं और प्रदेश आज प्रगति के नये–नये प्रतिमान स्थापित कर देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है।

उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में प्रगति हुई है तो किसानों की प्रगति हुई है, नौजवानों, महिलाओं की, गरीबों की, वंचितों की प्रगति हुई है।

आज डबल इंजन की सरकार का लाभ सबको दिखाई दे रहा है। हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से प्रधानमंत्री मोदी जी के मूलमंत्र को अंगीकार करते हुए गांवों के विकास, गरीबों के उत्थान, किसानों की खुशहाली, युवाओं के रोजगार और मातृशक्ति की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। भाजपा की डबल इंजन सरकार ने विकास सबका किया लेकिन तुष्टिकरण के लिए को जगह नहीं है ।इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक फिर जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम प्रचार में निकल रहे हैं तो इंद्रदेव भी वर्षा के रूप में अपना आशीर्वाद दे रहे हैं।

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार में किसी दुकान या दुकानदार से कोई गुण्डा न गुण्डई कर सकता है और न वसूली कर सकता है। भाजपा सरकार ने गुण्डागर्दी समाप्त करने का काम किया है। भ्रष्ट, बेईमान, गुण्डा व अपराधियों की सम्पत्ति पर योगी सरकार का बुलडोजर चलता रहेगा। आज हम जनता के बीच प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी व मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व को लेकर हम जनसमर्थन प्राप्त करने जा रहे हैं। भाजपा ने जो कहा है वो किया है। एक बार फिर हम जनता के आशीर्वाद से 300 प्लस सीटें जीतेगें और गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं, वंचितों के कल्याण के लिए काम करते रहेंगे।

उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उन्होंने कहा कि 10 मार्च के बाद भी प्रदेश से दंगाइयों, माफियाओं, गुंडों, भ्रष्टाचारियों का पलायन जारी रहेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश को तरक्की पसंद है, जो भाजपा की सरकार ही दे सकती है।

उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में प्रगति हुई है तो किसानों की प्रगति हुई है, नौजवानों, महिलाओं की, गरीबों की, वंचितों की प्रगति हुई है। 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश की प्रगति हुई है। आज उत्तर प्रदेश वासियों को पलायन के लिए मजबूर करने वाले आज खुद पलायन को मजबूर हैं। भाजपा सरकार में, पलायन हुआ है तो माफियाओं का, दंगाईयो का, गुंडों का, व्यभिचारियों का, भ्रष्टाचारियों का पलायन हुआ है। ऐसे लोगों का पलायन उत्तर प्रदेश में जारी रहेगा, क्योंकि यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार।■

''यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार''

जो कहा, सो कर के दिखाया और यह तब किया, जब सोच ईमानदार और काम दमदार है। न वंशवाद, न जातिवाद, न दंगा फसाद। सबको सुरक्षा और सबको संवृद्धि देने का भाव यह कोई पैदा कर सकता है, तो केवल भाजपा कर सकती है।

भारत की आस्था का सम्मान नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से अविरल गंगा, निर्मल गंगा। भव्य और दिव्य कुंभ। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। काशी विश्वनाथ धाम भी डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में करके दिखाया है। सीएम ने कहा कि प्रदेश की बेटियों और माताओं को सुरक्षा का बेहतर वातावरण भी भाजपा सरकार ने दिया। जो माफिया सत्ता का शागिर्द बनकर गरीबों, व्यापारियों, संभ्रांत लोगों का जीना हराम करते थे। बहन–बेटियां जिन माफियाओं के कारण घर से बाहर नहीं निकल पाती थीं, उन माफियाओं के घरों पर, उनकी अवैध और अनैतिक कमाई पर बुलडोजर चलाने का भी काम किया है। आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि हमने जो कहा था, सो कर दिखाया।

वंशवादी और परंपरागत जातिवादी राजनीति को चुनौती

पांच वर्ष पहले हम अपने संकल्प के साथ आगे बढ़े थे, तब हमने राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मार्ग से अंत्योदय के मार्ग को प्राप्त करने का एक संकल्प लिया था। भाजपा सरकार ने उन सभी संकल्पों को पूरा किया। राष्ट्रवाद के मूल्यों पर बिना डिगे, बिना झुके, बिना हटे, वंशवादी और प्रदेश की परंपरागत जातिवादी राजनीति को खारिज करते हुए प्रदेश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की स्थापना में सरकार ने न केवल अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करके प्रदेश की आस्था को सम्मान दिया।

निवेश और रोजगार के सृजन

यह उत्तर प्रदेश ही कर सकता था कि जो दंगाई कभी प्रदेश की शांति और सौहार्द्र के लिए खतरा बने हुए थे और बाद में सत्ताधारी दल उनका आवभगत करते थे। आज उन्हीं दंगाईयों के पोस्टर सार्वजनिक स्थानों पर लगाकर, उन्हीं दंगाईयों की सार्वजनिक संपत्ति की वसूली कर एक नजीर भी प्रदेश ने प्रस्तुत की है। प्रदेश में सुरक्षा का बेहतर वातावरण हमारी सरकार ने दिया। सुरक्षा के माहौल ने प्रदेश में निवेश और रोजगार के सृजन को भी आगे बढ़ाया। प्रदेश में एक बेहतरीन माहौल देने का कार्य न केवल निवेश की दृष्टि से, बल्कि बिना भेदभाव के प्रत्येक को सुरक्षा, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं हुआ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूलमंत्र को अपना

ध्येय वाक्य मानते हुए प्रदेश सरकार ने कार्य किया और आज उसका परिणाम है कि विकास की योजनाओं का लाभ सबको, विकास सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं हुआ। पिछली सरकारों में मुख्यमंत्री और मंत्री अपना मकान बनाते थे, लेकिन मुझे इस बार पर गौरव की अनुभूति होती है कि डबल इंजन की सरकार ने 43 लाख गरीबों को एक–एक मकान दिया है।

लाभ किसानों को

36 हजार करोड़ का 86 लाख किसानों का कर्ज माफी का कार्यक्रम भी भाजपा ने किया। यही नहीं, सपा, बसपा फिर सपा की सरकारों में चीनी मिलें बंद होती थीं। हजारों करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का बकाया भी वर्षों लंबित रहता था। हमारी सरकार पांच साल में एक लाख 55 हजार करोड़ का भुगतान भी कर चुकी है। कोरोना के बावजूद इस साल 55 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद सीधे किसानों से करते हुए 10 हजार करोड़ का भुगतान किया गया है। एमएसपी का लाभ किसानों को भाजपा सरकार ने दिया।

भाजपा इसलिए आवश्यक है, जिससे प्रदेश में कानून का राज हो, हिस्ट्रीशीटर थाने ना चलाएं, अपराधी सरकार ना चलाएं, भ्रष्टाचार पर अंकुश बना रहे, माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चलता रहे, दंगाइयों को सख्त सजा दी जा सके, तुष्टिकरण की राजनीति ना हो, सरकारी भर्ती में पारदर्शिता बनी रहे, गरीबों को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, बिजली निर्बाध 24 घंटे मिलती रहे

एक्सप्रेस वे जीवन की रफ्तार बढ़ा सकें, बहन–बेटियों के सम्मान के साथ कोई गुंडा खिलवाड़ न कर सके, आगे भी इंसेफेलाइटिस और कोरोना जैसी महामारी को हराया जा सके, किसानों को उनकी उपज का पूरा दाम और सम्मान मिल सके, 'हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो सके, निवेश आता रहे और उद्योग धंधे विकसित हो सकें, रोज़गार सबको अपने घर के पास मिल सके। इसलिए भाजपा आज प्रदेश की आवश्यकता है।■

किसान हितैषी सरकार

– समीर सिंह

भाजपा सरकार इकलौती ऐसी सरकार है 2017 में जिसकी सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में ही 86 लाख किसानों के 36 हजार करोड़ के ऋण माफ किये गए।

किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सरकार ने हर स्तर पर प्रयास किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 2 करोड़ 53 लाख 98 हजार किसानों के खाते में 37,388 करोड़ हस्तांतरित किये गए हैं। पिछले साढ़े चार सालों में किसानों से 435 लाख मीट्रीक टन खद्यान खरीदे कर 79 हजार करोड़ का भुगतान किया। 2007 से 2017 के बीच केवल 221.07 लाख मीट्रीक टन खद्यान खरीदा गया था। आंकड़े बताते हैं कि किसान हितैषी कौन है?

तिलहन, दलहन, गेहूं, धान और अन्य दूसरी फसलों के एमएसपी में डेढ़ से दो गुना तक की बढ़ोतरी की गई है। हमने जहां गन्ना किसानों को पुराने बकाए के साथ ही डेढ़ लाख करोड़ का भुगतान किया, वहीं गन्ने के समर्थन मूल्य में भी इजाफा किया। जबकि सपा बसपा सरकार मिलकर भी 95 हजार करोड़ से ज्यादा का भुगतान नहीं कर पाई थी। कहा कि जिन्होंने चीनी मिलों को बंद कर कौड़ियों के भाव बेच दिया आज वे किसान हितैषी होने की बात कहते हैं तो मन में पहला भाव संदेह का ही उत्पन्न होता है।

सरकार ने किसानों के बिजली बिल भी हॉफ किये हैं, यह बहुत ही दूरगामी निर्णय है।किसानों को निर्बाध बिजली के लिए अलग से कृषि फीडरों का निर्माण किया गया है। जिसपर 10 घंटे की निर्बाध सप्लाई दिन में दी जा रही है, जिससे किसानों को रात में जगकर सिंचाई नहीं करनी पड़ती। पहले तो किसानों को बिजली मिलती ही नहीं थी। किसानों के ट्यूबवेल के बिल आधे किये गए,1.5 लाख किसानों को ट्यूबवेल के कनेक्शन दिए गए। जबकि सपा सरकार में डार्क जोन के नाम पर किसानों का उत्पीड़न किया गया और कनेक्शन रोके गए।

पिछले 40–50 वर्षों से लंबित अर्जुन सागर परियोजना, सरयू नहर परियोजना और ऐसी ही 17 अन्य सिंचाई की परियोजनाओं को पूर्ण किया गया। बेहतर सिंचाई और कृषि उपज को बढ़ावा देने के लिए, पहाड़ी बांध, बंदाई बांध, जमरार बांध, मोधा बांध, पौनी बांध, लहचुरा बांध, गुंटा बांध, रायसन बांध परियोजना और झाकलां पंप नहर का काम पूरा किया गया।बुंदेलखंड में पानी और सिंचाई की बेहतर व्यवस्था के लिए केन बेतवा लिंक परियोजना को मंजूरी दी गई। 1.50 लाख किलोमीटर नहरों का जीर्णोद्धार का काम किया गया। आज नहरों को टेल तक पानी मिलता है। 69050 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित की गई है, 2000 नये राजकीय नलकूपों के निर्माण से तथा 1000 असफल राजकीय नलकूपों का जीर्णोद्धार कर 10 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है।

2016–17 में यूपी ने केवल 277.69 लाख टन दूध का उत्पादन किया जो 2020–21 में बढ़कर 318.63 लाख टन उत्पादन हो गया। आज राज्य में बढ़ते दूध उत्पादन से रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। पिछले चार वर्षों में उत्तर प्रदेश ने 1,242.37 लाख मीट्रिक टन दूध का उत्पादन किया है। अमूल समेत छह बड़े कंपनियों ने 172 करोड़ रुपये का निवेश किया है। डेयरी उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, बरेली, कन्नौज,गोरखपुर, फिरोजाबाद, अयोध्या और मुरादाबाद में ग्रीनफील्ड डेयरियां स्थापित की जा रही हैं। झांसी, नोएडा, अलीगढ़ और प्रयागराज में चार पुरानी डेयरियों को अपग्रेड किया जा रहा है।

12 लाख दुग्ध किसानों/दूधधारियों को क्रेडिट कार्ड दिया गया है। 271 करोड़ रुपये के लागत से प्रदेश के सभी जिलों में गोरक्षा केंद्र (गौशाला) स्थापित किये गए। मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश सहयोग योजना के तहत

66,000 से अधिक गायों को इच्छुक पशुपालकों को सौंपा गया है। राज्य में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए गौ संरक्षण केंद्र और एक श्गोवंश वन विहारश् बनाये जा रहे हैं। 118 केंद्रों का निर्माण पहले ही पूरा हो चुका है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 2376 करोड़ रुपये क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया है। किसानों को 4 लाख 72 हजार करोड़ रुपये का फसली ऋण का भुगतान किया गया है। 45 कृषि उत्पाद मंडी शुल्क से मुक्त किया गया है। मंडी शुल्क 1 प्रतिशत घटाया गया है। 220 नये मण्डी स्थलों का निर्माण किया गया। 27 मंडियों का आधुनिकीकरण किया गया। 291 ई–नाम मंडी की स्थापन की गयी।मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना हेतु 500 करोड़ का प्रावधान है। इसका लाभ पट्टेदारों एवं बटाईदारों को भी मिलेगा। किसानों के बीच 3.76 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड एवं 2 करोड़ 03 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किया गया है। किसानों को रियायती दरों पर फसल ऋण उपलब्ध कराने के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

प्रदेश सरकार की मदद से मिलियन फार्मर्स स्कूल के तहत 5 लाख से अधिक किसानों को आधुनिक खेती के तौर तरीकों पर प्रशिक्षित किया गया। प्रदेश के 59 लाख किसान ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई योजना से लाभान्वित। स्प्रिंकलर सिंचाई योजना अंतर्गत 2 लाख 49 हजार स्प्रिंकलर सेट का वितरण किया गया है। पिछले साढ़े चार सालों के अंदर यूपी को 20 कृषि विज्ञान केंद्रों का मिला सौगात मिली है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के किसान हितैषी कार्यों में यूपी देश के अग्रणी राज्यों में है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश को देश में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। प्रधानमंत्री स्वनिधि

तिलहन, दलहन, गेहूं, धान और अन्य दूसरी फसलों के एमएसपी में डेढ़ से दो गुना तक की बढ़ोतरी की गयी है। हमने जहां गन्ना किसानों को पुराने बकाए के साथ ही डेढ़ लाख करोड़ का भुगतान किया, वहाँ गन्ने के समर्थन मूल्य में भी इजाफा किया।

योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान मिला है।

गन्ना, चीनी, एथेनॉल एवं सेनेटाइजर उत्पादन में लागातार चौथी बार देश में प्रथम 1.44 लाख करोड़ रुपये गन्ना मूल्य भुगतान कर देश में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। खाद्यान्न उत्पादन, गेहूं, आलू, हरी मटर, आम, आंवला और दुग्ध उत्पादन में देश में नंबर वन राज्य का गौरव आज यूपी को है।

कोरोना काल में सर्वाधिक खद्यान निःशुल्क वितरण करने वाला राज्य तिलहन उत्पादन में देश में प्रथम राज्य यूपी बना। किसानों को देय अनुदान को डीबीटी के माध्यम से माध्यम से भुगतान करने वाला प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश बना है। किसानों के लिए बाजार को व्यापक बनाने हेतु मंडी अधिनियम संशोधन करके वाला पहला राज्य भी यूपी ही बना है।■

125वीं जयंती विशेष

'नेताजी सुभाष बोस'

– डॉ. पवन सिंह

'बिना कीमत चुकाए कुछ हासिल नहीं होता और आज़ादी की कीमत है शहादत' आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को इस आह्वान के साथ 'तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा' नारे के द्वारा प्रेरित करने वाले व्यक्तित्व का नाम है सुभाष बोस. जय हिंद तथा दिल्ली चलो की प्रेरणा थे सुभाष। महात्मा गांधी को 'राष्ट्रपिता' का सर्वप्रथम संबोधन देने वाले व्यक्ति का नाम है सुभाष। बहादुरी –साहस–संकल्प– राष्ट्र भक्ति के जीते जागते आदर्श पुरुष थे नेताजी। राजनीति, कूटनीति व सैन्य शक्ति तीनों आज़ादी के लिए जरुरी है इस संकल्पना के प्रणेता थे बोस. अपने देश की आज़ादी के लिए पहली बार देश के बाहर जाकर फौज तैयार करने वाले शख्स थे सुभाष। भारत बोध की भावना को लाखों –लाखों युवाओं के दिलों की धड़कन बनाने वाले व आज़ादी के सबसे बड़े नायक का नाम है नेताजी सुभाष चंद्रबोस ।

अखंड व अविभाजित भारत के पहले प्रधानमंत्री: 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में बनाई गयी आज़ाद हिंद सरकार के सुभाष बोस प्रथम प्रधानमंत्री थे. यह भारत की अपनी सरकार थी, जिसे अन्य देशों जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन मानचुको, आयरलैंड आदि देशों का भी समर्थन प्राप्त था. इस आज़ाद हिंद सरकार का अपना बैंक 'आज़ाद हिंद बैंक', अपना डाक टिकट, अपनी मुद्रा, अपना गुप्तचर तंत्र था। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय झंडा, जन–गण–मन भारत का राष्ट्रीय गान होगा यह निर्णय भी सर्वप्रथम आज़ाद हिंद सरकार का ही था। इस सरकार का बर्मा की राजधानी रंगून में अपना मुख्यालय भी स्थापित था। यह वही आज़ाद हिन्द फौज थी जिसके सैनिकों ने भारत व भारत से बाहर भी अंग्रेजों की जड़ों को हिला कर रख दिया था. जिसके नाम से गोरे थरथर कांपते थे।

रेड फोर्ट ट्रायलः 1945 के बाद आज़ाद हिंद फौज के तीन ऑफिसर प्रेम सहगल, शाहनाज़ खान व गुरबक्श सिंह ढिल्लो पर अंग्रेजी हकूमत की बगावत व विद्रोह करने के खिलाफ लाल किले में नवंबर 1945 से जनवरी 1946 तक मुकदमा चला। आईएनए पर चलाए गए दस मुकदमों में से यह पहला मुकदमा था. यह मुकदमा पूरे देश में कौमी एकता की मिसाल बना. तीनों अफसरों की रिहाई के लिए देश भर में दुआएं की जाने लगी, धरने प्रदर्शन हुए, प्रार्थना सभाएं आयोजित हुई। मुकदमे के ट्रायल के दौरान देश के प्रत्येक व्यक्ति तक आज़ाद हिन्द फौज के संघर्ष की कहानियों ने देशभक्ति का माहौल निर्माण कर दिया। इस ट्रायल ने अपनी आज़ादी के लिए लड़ने वालों को अपने अधिकारों के प्रति जागरुक कर दिया था. आखिरकार इस ट्रायल से निर्मित वातावरण से अंग्रेज हवा का रुख पहचान गए थे और उन्होंने तीनों अफसरों को रिहा कर दिया।

सैनिक– सा जुझारूपन और राजनेता –सी व्यापक दृष्टिः भारत में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन को एक आर या पार के युद्ध का रूप देने वाले थे नेताजी। अहिंसा आंदोलन में भाग लेकर सुभाष को इस बात का स्पष्ट संकेत मिल गया था कि अंग्रेजों को आर – पार की भाषा ही समझ

आएगी। इसलिए उन्होंने गांधी जी का साथ छोड़ दिया। मुसोलिनी और हिटलर से मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध करने का पक्ष रखना और जापान में 'आज़ाद हिंद फौज' की स्थापना कर दिल्ली कूच करना नेताजी के व्यक्तित्व के वे पहलू हैं, जो सिर्फ सुभाष में ही थे, उस समय के किसी अन्य राजनेता में नहीं थे। उस समय नेताजी द्वारा रेडियो पर दिया गया संदेश आज भी सार्थक है– 'किसी अंग्रेज के सामने हमारे देशवासियों को सर झुकाने की जरुरत नहीं। यदि किसी का सर झुकेगा, तो फिरंगी हमारे देश के स्वाभिमान पर हंसेंगे। इसलिए आप लोग उन्हें हंसने का मौका न दें। हम कल भी सिर उठाकर जी रहे थे, आज भी सिर उठाकर जी रहे हैं और मरते डैम तक सिर उठाकर ही जीते रहेंगे'।

स्वतंत्र भारत की अमरता का जयघोष करने वाली राष्ट्रप्रेम की दिव्य ज्योति जलाकर सुभाष बोस अमर हो गए।

नेताजी और आज़ाद हिंद फौज के खौफ से मिली आज़ादीः सन 1956 में ब्रिटेन के तात्कालिक प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली भारत आए। ये वही एटली थे जिन्होंने भारत की आज़ादी के ड्राफ्ट पर 1947 में हस्ताक्षर किये थे। जब इनसे पूछा गया की 1942 भारत छोड़ो आंदोलन की विफलता एवं 1945 में द्वितीय विश्वयुद्ध जीतने के बावजूद भी आप भारत को इतनी जल्दी छोड़ने के लिए क्यों तैयार हो गए? एटली का उत्तर था, इसके पीछे का कारण थे सुभाष बोस व उनकी आज़ाद हिन्द फौज. जिसके कारण पूरे देश भर में भारत की आज़ादी को लेकर इस प्रकार का माहौल पैदा हो गया था कि हमें समझ आ गया था कि अब हम भारत में ज्यादा समय तक टिक नहीं सकते। इसी कारण हमें भारत को आज़ाद करने पर विवश होना पड़ा।

वास्तव में बोस अद्भुत नेतृत्व क्षमता व आज़ादी के संघर्ष में आउट ऑफ़ बॉक्स थिंकिंग रखने वाले दूरदृष्टा थे, जो युग से आगे की सोच रखते थे. कूटनीति चालें चलने व परिस्थिति अनुसार कूटनीति पूर्ण योजनाएं बनाने में उनका कोई सानी नहीं था। आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद सरकार, आज़ाद हिंद रेडियो स्टेशन एवं रानी झांसी रेजीमेंट उनके जीवन की विशेष उपलब्धियां थी, जो उनकी दूरदर्शिता का परिचायक बनी। उनका मानना था कि भारत की आज़ादी की इच्छा अगर हर भारतीय के मन में उठे, तो भारत को आज़ाद होने से कोई नहीं रोक सकता। स्वतंत्र भारत की अमरता का जयघोष करने वाली राष्ट्रप्रेम की दिव्य ज्योति जलाकर सुभाष बोस अमर हो गए। लेकिन उनके विचार, उनका जीवन आज भी प्रत्येक भारतीय के लिए पथ प्रदर्शक है। आज भी नौजवानों में सुभाष बाबू न केवल लोकप्रिय है बल्कि उनके प्रेरणा पुरुष व आदर्श भी है. तो आइये, बोस की 125 वीं जयंती के अवसर पर उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए, उनको व उनके जीवन को जन–जन तक पहुंचा कर इस राष्ट्र निर्माण के पुनीत कार्य में हम भी अपनी भूमिका को सुनिश्चित करें।

जय हिंद, जय भारत।।▪ .

इतिहास में उत्तर प्रदेश

– साधक राजकुमार

देश का सबसे बड़ा प्रदेश जहाँ से भारतीय संस्कृति विकसित हुई, जिसे पवित्र नदियों ने सींचा, जिसकी रखवाली पर्वतराज हिमालय करते हैं। उसके स्थापना दिवस मनाने की जब बात उठी तो मात्र कुल सात दशकों की आयु बताना लोगों को अटपटा लगा। जैसे भारत को कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा बनाया देश बताते हुए लगता हैं। जबकि भारत, सांस्कृतिक राष्ट्र के रूप . में दुनिया का प्राचीनतम् राष्ट्र है। भले अनेकों राजा, राज्य रियासतें, स्टेट रहे हों पर हमारी सांस्कृतिक एकता हमेशा

अक्षुण रही है। महर्षि पतंजली, जगदगुरू शंकराचार्य जैसे अनेकों पूज्य संतो महापुरूषों ने इसके लिये कठिन

तप किये। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में गुलामी के कालखण्डों में नवाबों, राजा रजवाड़ों ने अपनी सीमाएं छोटी रखीं। आपस में उलझते रहे, जिसके कारण नाम सीमाएं घटती बढ़ती रहीं पर यह प्रदेश भारत की मूल चिति आत्मा है।

उत्तर प्रदेश का इतिहास भारत के व्यापक इतिहास से बहुत जुड़ा हुआ है। यह 4000 वर्ष पुराना है। पूर्व में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आर्यों या दासों के कब्जे में था और उनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। विजय प्राप्त कर आर्यों ने आस पास के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। राज्य महाभारत युद्ध का केंद्र था। उन्होंने इस क्षेत्र में इसकी सभ्यता की नींव रखी। इस क्षेत्र में महाभारत, रामायण, ब्राह्मण और पुराणों के महाकाव्यों की रचना की गई थी। पहली सहस्राब्दीईसा पूर्व के मध्य में ऐसा समय था जब उत्तर प्रदेश ने भगवान बुद्ध के आगमन और बौद्धधर्म के प्रसार को देखा।

भगवान बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के सारनाथ में धामेक स्तूप में अपना पहला उपदेश मगध शासन के अधीन दिया था।

चौखंडी स्तूप यहाँ उस स्थान को चिन्हित करता है जहाँ भगवान बुद्ध अपने शिष्यों से मिले थे। कुरु के अलावा, पांचाल, वत्स और विदेह आदि ने राज्य के प्रारंभिक क्षेत्र का गठन किया। इन क्षेत्रों को मध्य देश के नाम से जाना जाता था। अशोक की भूमि का के दौरान, कई

लोक कल्याण कारी कार्य किए गए। मगध . साम्राज्य के शासन के दौरान , बौद्धधर्म और जैन धर्म इस क्षेत्र में विकसित हुए। यह प्रशासनिक और आर्थिक उन्नति का दौर था।

बाद में सत्ता को नंदा राजवंश और फिर मौर्यों में स्थानांतरित कर दिया गया। हालाँकि यह शहर हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान अपने गौरव के

शिखर तक पहुँच गया था। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर मुस्लिम शासन के आगमन से काफी प्रभाव पड़ा।

वह काल राजपूतों की अधीनता का गवाह था, जिसकी सत्ता राजस्थान के कुछ हिस्सों तक सीमित थी। उत्तर प्रदेश मुगल शासन के दौरान और विशेष रूप से सम्राट अकबर के शासन के दौरान समृद्धि के चरम पर पहुंच गया।

समय के साथ, उत्तर प्रदेश मुगल शासन की पतन शीलता और अंग्रेजों के आगमन का गवाह बना।

मुगल प्रभाव दोआब क्षेत्र तक ही सीमित रह गया था।

ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अवध के तीसरे नवाब के शासन काल के दौरान अवध शासकों के संपर्क में आई। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उत्तर प्रदेश का इतिहास ब्रिटिश शासन के दौरान और उसके बाद देश के इतिहास के साथ समवर्ती रूप से चला, लेकिन यह भी सर्वविदित है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में राज्य के लोगों का योगदान महत्वपूर्ण था।

उत्तर प्रदेश के इतिहास को पाँच कालों में बाँटा जा सकता है–प्रागैतिहासिक एवं पौराणिक काल (लगभग 600 ई.पू. तक), बौद्ध–हिन्दू (ब्राह्मण) काल (लगभग 600 ई.पू. से लगभग 1200 ई.), मुस्लिम काल (लगभग 1200 से 1775 ई.), ब्रिटिश काल (लगभग 1775 से 1947 ई.), स्वतंत्रता पश्चात् का काल (1947 से वर्तमान तक)। गंगा के मैदान के बीचोंबीच की अपनी स्थिति के कारण उत्तर प्रदेश समूचे उत्तरी भारत के इतिहास का केन्द्र बिन्दु रहा है। उत्तर वैदिक काल में इसे 'ब्रह्मर्षि देश' या 'मध्य देश' के नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश वैदिक काल में कई महान् ऋषि–मुनियों, जैसे–भारद्वाज, गौतम, याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, विश्वामित्र और वाल्मीकि आदि की तपोभूमि रहा है। कई पवित्र पुस्तकों की रचना भी यहीं हुई। दो मुख्य महाकाव्य रामायण और महाभारत की कथा भी की है।

ईसा पूर्व छठी शताब्दी में उत्तर प्रदेश में दो नए पंथों– जैन और बौद्ध का विकास हुआ। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया और बौद्ध धर्म की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश के ही कुशीनगर में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। उत्तर प्रदेश के कई नगर जैसे– अयोध्या, प्रयाग, वाराणसी और मथुरा विद्या अध्ययन के लिए प्रसिद्ध केंद्र थे।

प्रागैतिहासिक एवं पौराणिक काल

पुरातत्त्व ने उत्तर प्रदेश की आरम्भिक सभ्यता पर नई रौशनी डाली है। दक्षिणी ज़िले प्रतापगढ़ में पाई गई मानव खोपड़ियों के अवशेष लगभग 10,000 ई.पू. के बताए गए हैं। वैदिक साहित्य और दो महाकाव्यों, रामायण व महाभारत से इस क्षेत्र के सातवीं शताब्दी ई. पू. के पहले की जानकारी मिलती है। जिसमें गंगा के मैदानों का वर्णन उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत किया गया है। महाभारत की पृष्ठभूमि राज्य के पश्चिमी हिस्से हस्तिनापुर के आसपास है, जबकि रामायण की पृष्ठभूमि पूर्वी उत्तर प्रदेश राज्य में भगवान राम का जन्मस्थान अयोध्या है। राज्य में दे अन्य पौराणिक स्रोत हैं–वृन्दावन व मथुरा के आसपास के क्षेत्र जहाँ कृष्ण का जन्म हुआ था।

रामायण में हिन्दुओं के भगवान राम का प्राचीन राज्य कौशल इसी क्षेत्र में था, अयोध्या कौशल राज्य की राजधानी थी। हिन्दू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु के आठवें अवतार भगवान कृष्ण का जन्म उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर में हुआ था। विश्व के प्राचीनतम नगरों में से एक माना जाने वाला वाराणसी शहर भी इसी प्रदेश में है। वाराणसी के समीप सारनाथ का स्तूप भगवान बुद्ध के लिए प्रसिद्ध है। समय के साथ साथ यह विशाल क्षेत्र छोटे–छोटे राज्यों में विभाजित हो गया और गुप्त, मौर्य और कुषाण साम्राज्यों का भाग बन गया। 7वीं शताब्दी में कन्नौज गुप्त साम्राज्य का प्रमुख केन्द्र बन गया था।

राज्य का इतिहास

400 ईसापूर्व के काल से नंद और मौर्य वंश ने जो साम्राज्य की परिधि बनाई उसके हृदय में शुंग, कुषाण, गुप्त, पाल, राष्ट्रकूट फिर मुगलों ने ये भू–भाग सुरक्षित बनाये रखा. यह राज्य सिर्फ हिन्दू संस्कृति नहीं बल्कि बौद्ध धर्म के प्रेरणादायी अतीत की गाथा की भूमि भी रहा है।

24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस

24 जनवरी 1950 से पहले यह राज्य यूनाइटेड प्रॉविंग के नाम से पहचाना जाता था। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश को उसका नाम मिला। यह 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश शासन के दौरान इसे संयुक्त प्रांत आगरा और अवध के रूप में स्थापित किया गया था। ब्रिटिश शासनकाल में इसे यूनाइटेड प्रॉविंस कहा जाता था जो कि 24 जनवरी 1950 में बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया।

उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य

जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। इस राज्य की जनसंख्या लगभग 22 करोड़ है। इस राज्य की जनसंख्या इतनी है कि अगर उत्तर प्रदेश एक राज्य न होकर स्वतंत्र देश होता तो कई आबादी के आधार पर यूपी चीन, भारत, अमेरिका, इण्डोनेशिया और ब्राज़ील के बाद छठा सबसे बड़ा देश होता। इस राज्य के जनसंख्या अनुपात की बात करें तो यहां 2011 की जनगणना के मुताबिक 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या 908 है।

वर्तमान में सबसे ज्यादा जिलों वाला राज्य उत्तर प्रदेश ही है। यहां कुल जहां 75 जिले हैं। दायरे के आधार पर लखामपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बडा जिला है। यूपी के बाद 52 जिलों वाले मध्य प्रदेश का नंबर आता है। महज दो जिलों के साथ गोवा सबसे कम जिलों वाला प्रदेश ह। इस राज्य की राजधानी लखनऊ है।

75 जिलों के अलावा राज्य को 18 मंडलों में बांटा गया है। ये अलीगढ़ मंडल, आगरा मंडल, आजमगढ़ मंडल, प्रयागराज मंडल, कानपुर मंडल, गोरखपुर मंडल, चित्रकूट मंडल, झांसी मंडल, देवीपाटन मंडल, अयोध्या मंडल, बस्ती मंडल, बरेली मंडल, मीरजापुर मंडल, मुरादाबाद मंडल, मेरठ मंडल, लखनऊ मंडल, वाराणसी मंडल और सहारनपुर मंडल हैं।

यह 243,290 वर्ग किलोमीटर (93,933 वर्ग मील) को कवर करता है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल के 7.33 प्रतिशत के बराबर है।

राज्य की भाषा और बोलियां –

उत्तर प्रदेश वैसे तो इतना बड़ा राज्य है कि यहां आपको कुछ ही दूसरी पर भिन्न–भिन्न बोली वाले लोग मिल जाएंग। वैसे इस राज्य की भाषा हिन्दी है। उत्तर प्रदेश की आबादी में 94.08 फीसदी लोग हिन्दी बोलते हैं। हिंदी भाषा के अलावा जैसा कि हम बता चुके हैं राज्य इतना बड़ा है कि इसमें कई तरह की बोली भी बोली जाती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में बोली जाने वाली अवधी, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भोजपुरी क्षेत्र में बोली जाने वाली भोजपुरी और ब्रज क्षेत्र के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली ब्रजभाषा शामिल हैं। उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया जाता है।

संस्कृति और साहित्य में समृद्ध –

यह राज्य कई धर्मों के संस्कृति का केंद्र है। वास्तुशिल्प, चित्रकारी, संगीत, नृत्यकला के लिए यह राज्य जानी जाती है। यह राज्य हिन्दुओं की प्राचीन सभ्यता का धरोहर है।यहां के कई आश्रमों में वैदिक साहित्य मन्त्र, मनुस्मृति, महाकाव्य–वाल्मीकिरामायण, और महाभारत के उल्लेखनीय हिस्से जीवंत हैं।

इस राज्य का संगीत से भी गहरा संबंध है। तानसेन और बैजू बावरा जैसे संगीतज्ञ मुग़ल शहंशाह अकबर के दरबार में थे, जो राज्य और समूचे देश में आज भी विख्यात हैं। भारतीय संगीत के दो सर्वाधिक प्रसिद्ध वाद्य सितार (वीणा परिवार का तंतु वाद्य) और तबले का विकास इसी काल के दौरान इस क्षेत्र में हुआ।

इसके अलावा भारतीय डांस ऑर्म की बात करें तो 18वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश में वृन्दावन और मथुरा के मन्दिरों में भक्तिपूर्ण नृत्य के तौर पर विकसित शास्त्रीय नृत्य शैली कथक उत्तरी भारत की शास्त्रीय नृत्य शैलियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इस राज्य के ग्रामीण श्रेत्रों के लोकगीत काफी मशहूर हैं।

साहित्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश की धरती पर एक से बढ़ कर एक लेखक और कवि पैदा हुए। गोस्वामी तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य राम चन्द्र शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला', सुमित्रानन्दन पन्त, मैथलीशरण गुप्त, सोहन लाल द्विवेदी, हरिवंशराय बच्चन, महादेवी वर्मा, राही मासूम रजा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय आदि कुछ ऐसे ही बड़े नाम हैं।

राजनैतिक दृष्टि से प्रभावी उत्तर प्रदेश 80 सांसद चुनता है, 403 विधायकों की समृद्ध विधानसभा, विधान परिषद के साथ प्रदेश की शासकीय व्यवस्था चलती है। भाजपा कॉंग्रेस, जैसे राष्ट्रीय दलों के साथ, सपा, बसपा जैसे दर्जनों क्षेत्रीय राजनैतिक दल यहाँ सक्रिय है। शिक्षा, संस्कृति, स्वावलम्बन, चिकित्सा विकास जैसे सभी क्षेत्रों में आजादी के बाद से प्रदेश प्रगति की राह पर है। भाजपा सरकार आने के बाद हर जिले को औद्योगिक पहचान मिली और अनेक लोगों की माँग पर पूर्व राज्यपाल, मा0 रामनाइक जी एवं योगी जी के विशेष प्रयास से स्थापना दिवस मनाने की परम्परा चल पड़ी है। हम अपने गौरवशाली अतीत को सहेजे, निरन्तर विकास के पथ पर अग्रसर हों यही शुभकामना!▪

'सुराज' लोकमंगल की शपथ

– हृदय नारायण दीक्षित

संन्यास और सत्ता के संयोग से लोकमंगल

उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय आकर्षण है। सामान्य राज्य नहीं। यह मानव जिजीविषा का धर्मक्षेत्र, कर्मक्षेत्र है। यह एक मधुमय काव्य है। एक अंतहीन कविता गर्व करने योग्य जीवंत इतिहास, प्रणाम करने योग्य भूगोल। वैदिक ऋचाओं के सामगान की धरती। विश्व वरणीय संस्कृति का उद्‌गम। श्री राम कथा का सृजन वाल्मीकि ने यहीं किया। व्यास ने वेद ज्ञान का सुव्यवस्थित विभाजन यहीं किया। विश्व की अति प्राचीन नगरी वाराणसी का मुद, मोद, प्रमोद और शिव उल्लास यहां है। काशी, मथुरा और श्रीराम की अयोध्या यहां है। यहीं ध्यान, उपासना, यज्ञ की पुण्य भूमि प्रयाग। गंगा, यमुना सरस्वती का तीर्थराज मिलन संगम भारत के प्राणों में रचा–बसा है। इसी पवित्र क्षेत्र में श्रृंगवेरपुर निषादराज का भवन।

प्रदेश अनेक प्रश्नोत्तरों की भूमि है, महाभारत के यक्ष प्रश्न यहीं रचे गए थे। प्रश्नकर्ता था यक्ष। उत्तरदाता धर्मराज युधिष्ठिर। **प्रश्न था–** 'कः पंथा – जीवन मार्ग क्या है? **युधिष्ठिर ने उत्तर दिया –** वेद वचन भिन्न–भिन्न। ऋषि अनेक, तर्क अपर्याप्त। धर्म तत्व गुहा में है। इसलिए श्रेष्ठजनों द्वारा अपनाया गया मार्ग ही उचित है– 'महाजनों येन गतः स पंथा'।

उत्तर प्रदेश प्राचीन काल से ही प्रश्न और जिज्ञासा का क्षेत्र रहा है। तब सृष्टि रहस्य की जिज्ञासा के प्रश्न थे। कर्मयोग, ज्ञान और भक्ति की त्रिवेणी थी। सुख, दुःख, ज्ञान, मुक्ति, भक्ति की जिज्ञासा थी। जीवन–जगत के सभी प्रश्नों के उत्तर थे। सो यह प्रदेश उत्तर प्रदेश था। लेकिन पांच साल के पहले कुछ समय तक यहां प्रश्नों का चरित्र बदल गया था। अपनाध बढ़े। निराशा बढ़ी। माफिया बढ़े। सदाचरण रोता रहा। कानून माफिया की गिरफ्त में था। प्रश्न डरावने थे। सत्ता डरा रही थी। फिर सत्ता में आये योगी आदित्यनाथ। लोकमंगल की शपथ लेकर उन्होंने कानून व्यवस्था की सुराज स्थापना की । उन्होंने विकास कार्य व समृद्धि का नया इतिहास रचा। संन्यास और सत्ता के संयोग ने प्रदेश को आनंदवर्धन बनाया है। प्रदेश के पास अब सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। उत्तर प्रदेश अब वस्तुतः समृद्ध और संकल्पबद्ध उत्तर प्रदेश है। आशा, महत्वाकांक्षा और सांस्कृतिक गतिशीलता की उड़ान भरता प्रदेश।

श्री राम अखिल लोकदायक विश्राम हैं। शील और मर्यादा के पुरूषोत्तम। वाल्मीकि की रामायण शील और आचार–विचार की दिव्यता का महाकाव्य है। रामकथा का प्रस्थान बिन्दु लोकमंगल है। वाल्मीकि शुरूआत में जिज्ञासा करते हैं। **को–अस्मिन साम्प्रतं**

लोके गुणवान – इस लोक में श्रेष्ठ गुणवान और शक्ति सम्पन्न कौन है? उन्हें उत्तर मिलता है **''श्रीराम इसी लोक में हैं और लोकोत्तर भी हैं। वह पुरुष भी हैं और पुरूषोत्तम भी।''**

इतिहास के माध्यकाल में तुलसी दास ने रामचरित मानस लिखा। तब भारतीय समाज उद्विग्न था। धर्मपालन कठिन था। तुलसीदास ने ऋग्वेद से लेकर मध्यकाल तक की धर्म धारणा को अपने सृजन का विषय बनाया। लिखा, 'जब–जब होई धरम की हानी/बाढ़हिं असुर अभिमानी/तब–तब प्रभु धरि मनुज शरीरा/हरहिं दयानिधि सज्जन पीरा।' तुलसी की अनुभूति में धर्म आचरण प्रथम है। उसकी हानि परम सत्ता को भी उद्वेलित करती है। परम सत्ता धर्म रक्षा के लिए मनुष्य शरीर धारण करती है। रामचरित मानस के अनुसार एक समय धर्म की हानि से पृथ्वी पर असुर बढ़े। पृथ्वी आहत हुई। सभी देव शक्तियां ब्रह्म के पास गए थे। तभी आकास से आश्वासन आया, हे पृथ्वी धैर्य धारण करों। मैं स्वयं यहां जन्म लूंगा और तुम्हारा संताप व असुरों को नष्ट करूंगा। रामचरित मानस इतिहास है। सरल–तरल काव्य है और अपनी लोकप्रियता व आस्था में धर्मशास्त्र भी है। रामचरित मानस ने छोटे–छोटे गांवों तक प्रभाव डाला। धर्म की रक्षा की।

अनादि काल से उत्तर प्रदेश के क्षेत्र ने जीवन–जगत के सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। परन्तु पांच वर्ष पर्वू तक यहां प्रश्नों का चरित्र बदल गया था। योगी आदित्यनाथ ने लोकमंगल की शपथ लेकर विकास व समृद्धि का नया इतिहास रचा। सन्यास और सत्ता के संयोग ने प्रदेश को आनंदवर्द्धन बनाया हे। प्रदेश के पास अब सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। उत्तर प्रदेश में ऋद्धि–सिद्धि, प्रसिद्धि का सांस्कृतिक झरोखा है। यह झरोखा पूरे देश को सांस्कृतिक प्रेरणा दे रहा है।

सप्तपुरियों में एक मथुरा का ध्यान

उत्तर प्रदेश में मथुरा सप्त महापुरियों में गिनी जाती है। यहीं वृन्दावन है। लगभर चार हजार मंदिर और सरोवर हैं। गोविन्ददेव मन्दिर का स्थापत्य भव्य है। इसी मन्दिर के सामने द्रविणशैली में श्वेद पत्थर का रंगनाथ मन्दिर है। यहीं गोवर्धन है, बरसाना कृष्ण की प्रिया राधा का जन्म स्थान है। इसी क्षेत्र में दाऊजी का मन्दिर है। दुनिया की किसी संस्कृति में नाचता–गाता देवता नहीं है, लेकिन कृष्ण ने ब्रजभूमि में गीत–संगीत की धारा बहाई। कृष्ण स्वयं वंशीवादक थे। संगीत के जीवमान प्रतिरूप भी थे। कृष्ण ने (10/35) गीता में स्वयं को वृहत्साम और गायत्री छंद बताया 'हे पार्थ गायन करने वाली श्रुतियों में मैं वृहत्साम हूं और छंदों में गायत्री छंद हूं।' काव्य और संगीत ही विष्णु के वाहन हैं। बललभ सम्प्रदाय में उपासना का माध्यम संगीत है। भक्ति काव्य गीत–संगीत, संस्कृति और धर्म का वाहक रहा है। कृष्ण की लीलाभूमि मथुरा–वृन्दावन में संगीत प्रधान देव उपासना लोकप्रिय हुई। यहीं कृष्ण लीला गान सम्प्रदाय के रूप में अष्टछाप कवियों की स्थापना हुई। अष्टछाप के कवियों में सूरदास, नंददास, कुम्भनदास, गोविन्द स्वामी आदि के नाम उल्लेखनीय है। भक्त स्वयं कविता लिखते थे और संगीत भी गाते थे। सूरदास स्वयं गायक भक्त थे। स्वामी हरिदास को राग–रागिनियां सिद्ध थीं, ब्रज क्षेत्र के दर्शन में काव्य और संगीत के ही दर्शन हैं। भारत का मन कृष्ण में रमता है।

परम चेतना सूक्ष्म रूप में उतरती है और स्थूल रूप में प्रकट होकर भक्तों को आनन्दित करती है। कविता भजन का स्वरूप नहीं होती। वह अरूप होकर भी सुनाई पड़ती है। संगीत उससे भी सूक्ष्म है। संगीत का अर्थ नहीं होता। कविता का अर्थ होता है। श्रीकृष्ण की बांसुरी और संतों के ऐसे ही संगीत

उपकरण लोगों को आनन्दित करते थे। यह सब उत्तर प्रदेश में घटित हो रहा था और अभी भी गीत गायन, वादन और नृत्य के रूप में हमारी सांस्कृतिक धारा में प्रवाहित है।

ब्रज क्षेत्र का रूपान्तरण

लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने इस क्षेत्र के विकास की कोई योजना नहीं बनाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे क्षेत्र को विकसित करने के लिए उत्तर प्रदेश ब्रजतीर्थ विकास परिषद का गठन किया है। मथुरा में राधा कुण्ड स्थित पर्यटक आवास गृह के लिए व अन्य विकास कार्यों के लिए 348.67 लाख रूपये की परियोजना घोषित की है। वृन्दावन मार्ग पर एन.एच.–2 से रूक्मिणी विहार तक ग्रीनबेल्ट के कार्य के लिए 154.95 लाख रूपये की घोषणा की है। मथुरा में कवि रसखान की समाधि के संरक्षण सौन्दर्यीकरण के लिए 246.36 लाख व श्रीकृष्ण जन्मभूमि के गेट नं0 3 से गोविन्दनगर की सड़क के सौन्दर्यीकरण के लिए 342.41 लाख रूपये स्वीकृत किए हैं।

श्रीकृष्ण जन्मस्थान के सामने मार्ग के विकास और सौन्दर्यीकरण के लिए 359.76 लाख रूपये स्वीकृत हुए हैं। मथुरा जंक्शन के पास पर्यटन सूचना केन्द्र के लिए 24.81 लाख रूपये स्वीकृत हुए हैं। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के सरोवरों व जलापूर्ति व्यवस्था के लिए 1752.21 लाख स्वीकृत किए गए हैं। वृन्दावन स्थित देवरहा बाबा घाट के निर्माण और पहुंच मार्ग के लिए 439.81 लाख स्वीकृत हो चुके हैं। गोवर्धन पर्वत में तलहटी परिक्रमा विकास के लिए 1750.76 लाख रूपये स्वीकृत हैं। गोकुल में आनन्द भवन पार्किंग के पास नए घाट का निर्माण और मुरली घाट पर होली चबूतरे के सौन्दर्यीकरण हेतु 226.64 लाख स्वीकृत हुए हैं। ऐसी तमाम अन्य योजनाएं भी हैं। ब्रज विकास परिषद सक्रिय है। समूचे ब्रज क्षेत्र का रूपान्तरण हो रहा है। मुख्यमंत्री स्वयं सभी योजनाओं की निगरानी कर रहे हैं।

ब्रज क्षेत्र भारतीय संस्कृति और धर्म का विशिष्ट केन्द्र रहा है। ब्रज क्षेत्र का तीर्थाटन आश्चर्यजनक परिवर्तन लाता है। पूरे देश के कृष्ण भक्त इन योजनाओं की प्रशंसा कर रहा है। पर्यटन सामान्य यात्रा है और तीर्थाटन इससे भिन्न है। हम तीर्थ से आत्मिक आनन्द लेकर लौटते हैं, लेकिन पर्यटन से लौटते समय हमारी आन्तरिक ऊर्जा में आनन्द नहीं होता। ब्रज क्षेत्र में दोनो का आनन्द है। यहां के तीर्थाटन से मन राधे–राधे हो जाता है। ब्रज विकास परिषद दोनों समूहों को आश्वस्ति और आनन्द देने का काम कर रही है। संतों ने इस क्षेत्र को अपनी मधुर वाणी से मधुमय बनाया है। यह सांस्कृतिक कर्म है, धर्म कर्म है। इससे सारी दुनिया में ब्रज क्षेत्र का आकर्षण बढ़ रहा है। सूरदास ने गाया भी है 'उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही'।

मथुरा, काशी और अयोध्या सर्वथा नए रूप में विकसित हो रही है। हम सब अयोध्या की नई दीवाली और ब्रज की नई होली का स्वाद ले चुके हैं। काशी नए रूप में विकसित हो रही है। उत्तर प्रदेश में ऋद्धि–सिद्धि, प्रसिद्धि का सांस्कृतिक वातायन है। यह वातायन पूरे देश को सांस्कृतिक प्रेरणा दे रहा है। ■

सुराज में अन्नदाता

कृषि देश प्रदेश की अर्थव्यवस्था का एक मजबूत आधार है। कृषि के बूते ही संकट काल में अर्थव्यवस्था को अवलंब मिलता है। भारत में कृषि वर्षा और कई अन्य कारकों पर निर्भर करती है परन्तु समय बदलने के साथ अन्न उपजाने वाले अन्नदाताओं की स्थिति बहुत ठीक नहीं रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अन्नदाताओं के इस दर्द को समझा और किसानों की परेशानियों को दूर करने में जुट गए। इसका संकेत योगी सरकार के बनते ही मिला जब 86 लाख लघु एवं सीमान्त किसानों पर बकाया 36 हजार करोड़ रूपये का फसल ऋण वितरित किया गया। गत 4 वर्षों में 2387.64 लाख मीट्रिक टन से अधिक कृषि उत्पादन हुआ। इसके साथ ही सरकार ने 45 कृषि उत्पाद को मंडी शुक्ल से मुक्त किया। मंडी शुल्क 1 प्रतिशत घटाया गया। किसानों को खेती के समय पैसा उपलबध कराने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को मुस्तैदी से लागू किया गया और 2.48 किसानों को अब तक इसका लाभ दिया गया।

खाद कारखाने का शुभारम्भ

योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के पूर्व से ही किसानों के हित में सोंचते रहे हैं। सांसद होने के दौरान 1998 से वे गोरखपुर में खाद कारखाने के लिए निरंतर संघर्षरत रहे और हर संसद के हर सत्र में इसके लिए मांग करते रहे। वर्ष 2014 में केन्द्र में मोदी सरकार का गठन होने पर उनके संघर्ष को मंजिल मिलने लगी और 22 जुलाई 2016 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गोरखपुर में नए खाद कारखाने का शिलान्यास किया। वर्ष 2017 में मुख्यमंत्री बनने पर योगी आदित्यनाथ ने इस दिशा में तेजी से काम कराया और अंततः नवंबर, 2021 में इस कारखाने से परीक्षण उत्पादन आरंभ हो गया। इस खाद कारखाने से प्रतिवर्ष 12.7 लाख मीट्रिक टन नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन होगा। बड़े पैमाने पर खाद उत्पादन से देश के सकल खाद आयात में भारी कमी आएगी।

खेती करने वाले किसानों को समय पर खाद बहुत मुश्किल से मिलती थी। वर्ष 2021 के कई महीने में केन्द्र सरकार द्वारा डीएपी खाद के लिए सब्सिडी 500 रू0 प्रति बोरी से, 140 प्रतिशत बढ़कर 1200रू0 प्रति बोरी करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से किसानों को अब डीएपी खाद पर 500 रूपये प्रति बोरी से बढ़कर 1200 रूपये प्रतिबोरी की सब्सिडी मिल रही है। किसानों को डीएपी की बोरी 2400 रूपये के बजाय अब 1200 रूपये में मिल रही है।

केन्द्र, राज्य के प्रयास

योगी आदित्यनाथ सरकार ने किसानों की दशा सुधारने के लिए केन्द्र सरकार की किसान संबंधी सभी योजनाओं को पूरी सिद्दत से उत्तर प्रदेश में लागू किया। 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' योजना के अंतर्गत 2.48 करोड़ किसानों को 32,500 करोड़ रूपये दिए गए। बीमा योजना में पहली बार बंटाईदारों को शामिल किया गया। इसके अंतर्गत किसाना को अधिकतम पांच लाख रूपये तक की बीमा सुरक्षा मिल रही है। 'प्रधानमंत्री फसल बीमा' योजना से दो करोड़ से अधिक किसान जुड़े हैं और इस योजना से 25.60 लाख से अधिक किसानों को 2,208 करोड़ रूपये की क्षतिपूर्ति दी गई है।

'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' योजना लागू होने के बाद काफी संख्या में ऐसे किसान थे जिन्हें कागजात की मामूली गड़बड़ी के कारण इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। बैंक रिकॉर्ड में कतिपय गड़बड़ी के कारण बहुत से किसानों का पेमेंट रिस्पांस लंबित था तो कुछ का भुगतान खाते में नहीं पहुंच रहा था। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष अभियान चलाकर किसानों की समस्याओं का निस्तारण कराया। कुल 3 लाख 70 हजार 85 शिकायतों में से अब महज 1158 मामले ही लंबित हैं। 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश को शीघ्र स्थान के लिए सम्मानित किया जा चुका है।

केन्द्र सरकार की योजना है कि 'स्वायल हेल्थ कार्ड' बनाए जाएं। इसके लिए उत्तर प्रदेश के 43 जनपदों में मिट्टी की जांच की प्रयोगशाला बनाई गई हैं। खेतों की मिट्टी की जांच करके किसानों को रिपोर्ट दी जाती है। इस रिपोर्ट से किसानों को काफी मदद मिल रही है।

सिंचाई की सुविधा

गत चार वर्षों में 3.77 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता में बढ़ोत्तरी की गई है और 46 वर्षों से लंबित बाण सागर परियोजना को पूरा किया गया है। ऐसे ही दशकों से अटकी सरयू नहर पहरियोजना से जल्द किसानों के खेतों में पानी पहुंचने वाला है। कृषि के लिए तालाब खोदवाये गए। जिन तालाबों को पाट कर कब्जा कर लिया गया था, उसे फिर से ठीक कराया गया। तालाब की संख्या बढ़ने से भूजल स्तर में सुधार हुआ। तालाब का जल कृषि एवं गाय–भैंसों आदि के भी काम आ रहा हे। 'वन ड्राप–मोर क्राप' के अंतर्गत कम पानी का अधिक से अधिक उपयोग किया जा रहा है। स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति पर बल दिया जा रहा है। केन्द्र सरकार की इस योजना के माध्यम से प्रदेश सरकार, लघु एवं सीमान्त किसानों को 90 फीसदी अनुदान पर स्प्रिंकलर उपलब्ध करा रही है। सामान्य किसानों को 80 फीसदी अनुदान पर स्प्रिंकलर दिया जा रहा है।

धान–गेहूं खरीद में रिकॉर्ड, नई जींसों की खरीद

किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य मिले, इसके लिए एमएसपी में लगभग दोगुना की वृद्धि की गई। किसानों से 433.86 लाख मी0 टन खाद्यान्न खरीद पर 66 हजार करोड़ रूपये से अधिक का भुगतान किया गया। वर्ष 2020–21 में 66.84 लाख मी0टन धान की खरीद की गई। गत 4 वर्षों में 2387.64 लाख मीट्रिक टन से अधिक कृषि उत्पादन हुआ।

प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने से पहले केवल गेहूं और धान की खरीद की जाती थी। धान और गेहूं की वर्ष 2017 में रिकार्ड खरीद करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार हर वर्ष अपने ही बनाए हुए रिकार्ड तोड़ रही है। परंतु पहल बार प्रदेश सरकार ने उड़द और मूंग की दाल की खरीद भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर की। प्रदेश सरकार ने पहले ही वर्ष अर्थात साल 2017 में 40 हजार मीट्रिक टन उड़द खरीदा।

किसानों को नवीनतम यांत्रिक अविष्कारों का लाभ मिले, इसके लिए सरकार ने 158 करोड रूपये का अनुदान देते हुए दलहन और तिलहन किसानों को साढ़े चालीस हजार कृषि यंत्र वितरित कराए। प्रदेश में औद्यानिक खेती में भी काफी प्रगति हुई है। 7 जनपदों में यह खेती की जा रही है।

बिचौलियों से बचाव और बीमा

प्रदेश में फसल बीमा योजना को लागू किया गया। फसल बीमा योजना लागू कराने के साथ ही उस बीमा कंपनी का कार्यालय जिला मुख्यालय पर खुलवाया गया। इसके पहले बीमा कंपनी जिला मुख्यालय पर अपना कार्यालय नहीं खोलती थी, विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता था।

बिचौलियों से किसानों को बचाने के लिए 100 मंडियों को आनलाइन किया गया है। इन मंडियों में किसान सीधे तौर पर अपना उत्पाद बेच सकते हैं। आनलाइन बिक्री करने के लिए यूनीफाइड लाइसेंस का शुल्क 1 लाख रूपए से घटाकर 10 हजार रूपये कर दिया गया है।

सोलर पम्प पर अनुदान

प्रदेश के जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है, वहां पर मौसमी सब्जियों की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए 20 हजार सोलर पम्प लगवाये गए। दो से तीन हार्स पावर के सोलर पम्प 70 प्रतिशत अनुदान पर दिए गए। 5 हार्स पावर का सोलर पम्प 40 प्रतिशत अनुदान पर दिया गया। सोलर पम्प में सूर्य की ऊर्जा का बेहतर इस्तेमाल हो पा रहा है और बिजली की भी बचत कराई जा रही है। सोलर पम्प लग जाने से किसानों की सिंचाई की स्थायी व्यवस्था हो गई है।

मंडी समितियों की नई कार्य संस्कृति

योगी सरकार ने कर चोरी और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टालरेंस नीति अपनाते हुए मंडी परिषद के कामकाज को एक नई संस्कृति दी। मंडी समितियों के कामकाज को पूरी तरह पारदर्शी बनाया गया। वर्षों से मंडी को अपने कब्जे में रखने वाले बिचौलिये और आढ़तियों को बाहर कर किसानों को सीधे मंडी से जोड़ दिया गया। अब किसान सीधे अपनी फसल मंडियों में बेच कर ज्यादा लाभ कमा रहे हैं। कोरोना काल के दौरान किसानों को बड़ी राहत देते हुए 45 कृषि उत्पादों को गैर अधिसूचित कर मंडी शुल्क से मुक्त किया गया। मंडी शुल्क को 2 प्रतिशत से घटाकर किसानों के हित में 1 प्रतिशत किया गया। मंडी परिसरों के बाहर के व्यापार को पूरी तरह से लाइसेंस व मंडी शुल्क से मुक्त कर दिया गया है ताकि किसान अपना उत्पाद कहीं भी और किसी भी व्यापारी को अपनी कीमत पर तत्काल बेंच सकें। प्रदेश की 27 प्रमुख मंडियों को राइपनिंग चैम्बर, कोल्ड चैम्बर और आधुनिक सुविधा के लिहाज से विकसित करते हुए आधुनिक किसान मंडी के रूप में विकसित किया जा रहा है।

पिछली सरकारों में भ्रष्टाचार और घाटे की पहचान बन चुकी मंडी समितियां अब न सिर्फ लाभ कमा रही हैं बल्कि

किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के अभियान की अहम कड़ी साबित हो रही है। मंडी परिषद के आंकड़ों के अनुसार, 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में मंडी परिषद की कुल आय 1,210 करोड़ रूपये थी जबकि वित्तीय वर्ष 2018–19 में आय का आंकड़ा बढ़कर 1,822 करोड़ रूपये हो गया। वित्त वर्ष 2019–20 में मंडी समितियों की कुल आय का आंकड़ा बढ़कर 1,997 करोड़ रूपये तक पहुंच गया। वित्तीय वर्ष 2020–21 में कोरोना महामारी के बावजूद दिसम्बर 2020 तक मंडी समितियों की आय 802 करोड़ रूपये रही।

गन्ना किसानों के हित की मुहिम

उत्तर प्रदेश में अब इथेनॉल के जरिए गन्ने को 'ग्रीन गोल्ड' बनाया जाएगा। गन्ने से इथेनॉल बनाने के लिए 54 परियोजनाएं और लगाई जाएंगी। इथेनॉल बनाने की 54 परियोजनाओं में से 27 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं, जबकि 27 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इससे 25 लाख से अधिक किसानों को लाभ होगा। केन्द्र सरकार ने इथेलॉल को मानक ईंधन घोषित किया है। ऐसे में अब इथेनॉल की मांग में वृद्धि होगी। उत्तर प्रदेश में प्रति वर्ष 126.10 करोड़ लीटर इथेनॉल बनाया जाता हे। राज्य में करीब 50 आसवानियां इथेनॉल बना रही हैं। इस वर्ष इथेनॉल बनाने संबंधी नई परियोजना में उत्पादन शुरू होने से इथेनॉल उत्पान में प्रदेश, देश में सबसे ऊपर होगा और राज्य के किसानों को भी इसका लाीाा मिलेगा। गन्ना बेचने वाले किसानों को उनके गन्ने का भुगतान पाने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा और किसान गन्ना की फसल बोने से संकोच नहीं करेंगे।

अब गन्ना किसानों को कागज की पर्ची की जगह उनके मोबाइल फोन पर पर्ची एसएमएस के रूप में मिलने लगी है। उत्तर प्रदेश के लगभग 45 लाख गन्ना आपूर्तिकर्ता किसानों को समय से एसएमएस गन्ना पर्ची उपलब्ध कराई गई। ऑनलाइन पोर्टल 'केनयूपी.इन' एवं 'ई–गन्ना' ऐप के माध्यम से सर्वे, कैलेंडर, पर्ची और भुगतान सम्बन्धी सूचना प्रदेश के गन्ना किसानों को समय पर उपलब्ध हो रही है। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ई.आर.पी.) से पर्ची निर्गमन के कार्य में पूरी पारदर्शिता लाई गई है। 167 सहकारी गन्ना समितियों के वित्तीय लेन–देन, कृषि निवेशों का वितरण, किसानों को ऋण एवं अनुदान वितरण एवं गन्ना मूल्य भुगतान आदि को पारदर्शी बनाया गया। प्रदेश के 44.40 लाख कृषकों ने 'ई–गन्ना' ऐप डाउनलोड किया, 16.48 करोड़ बार किसानों ने केनयूपी. इन वेबसाइट पर अपनी सूचना को देखा।

प्रदेश में रमाला, पिपराइच, मुण्डेरवा चीनी मिलों सहित 20 चीनी मिलों का आधुनिकीकरण किया गया। कोरोना महामारी में खेती – किसानी से जुड़ी हर गतिविधियों को अनुमति दी गई ताकि किसानों को किसी प्रकार समस्या न हो। आज प्रदेश खेती किसानी के सहारे प्रगतिपथ पर अग्रसर है।■

सुराज में आत्मनिर्भरता के लिए स्टार्टअप

– डॉ हरनाम सिंह

आत्मनिर्भर भारत अभियान सिर्फ व्यापार एवं उद्योग का विषय नहीं है, इस संकल्पना के पीछे आत्मबोध के साथ ही शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक जागरण भाव है । "आत्मनिर्भर भारत" का उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक को हर प्रकार से सबल, सशक्त, सक्षम एवं समर्थ बनाना है जो भविष्य में आने वाली किसी भी संकट पर विजय प्राप्त कर सकें इसका ध्येय युवाओं के अंदर वह योग्यता दृढ़ता व साहस पैदा करना है जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था भौतिक एवं तकनीकी विकास के लिए आवश्यक स्वावलंबी तंत्र स्थापित कर सकें। सशक्त दृसमृद्ध आत्मनिर्भर होने के लिए स्वदेशी को युगानुकुल और विदेशी को स्वदेशानुकुल बनाकर संयोजित करना होगा । आत्मनिर्भर भारत बनाने की पहल के साथ स्टार्टअप, कौशल विकास, रोजगार सृजन के माध्यम से देश के युवाओं में उद्यमिता के आत्मबोध का भाव भरना होगा।

कोविड काल में अर्थव्यवस्था

कोविड काल में भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है फिर भी महामारी के समय में कई देशों को आर्थिक व अन्य मदद पहुंचाने वाला देश बना है। 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री ने देश की जीडीपी के 10 प्रतिशत के बराबर यानी 20 लाख करोड़ रूपये की राहत पैकेज की घोषणा की। रिजर्व बैंक ने भी वित्तीय व्यवस्था में नगदी की कमी न हो ऐसी व्यवस्था की है। सरकार ने कोविड से मंद पड़े उद्योग को आर्थिक सहायता के साथ ही पहलुओं पर भी विचार किया है। जिससे वित्तीय संस्थान, उद्यमी, व्यापारी, किसान और नए रोजगार को सृजन करने वाले संस्थानों को प्रभावी रूप से इस आत्मनिर्भर अभियान में अग्रसर किया जा सकें।

आत्मनिर्भरता के लिए कौशल विकास

भारत ने विश्व की एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति के तौर पर पहचान बनाई है । डिजिटल क्षेत्र में तो देश तेजी से आगे बढ़ा है । राष्ट्रिय शिक्षा नीति के माध्यम से आवश्यक कौशल प्रशिक्षित युवकों को तैयार करने सार्थक पहल हुई है । डिजिटल क्षेत्र के साथ डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजाइन थिंकिंग, शिक्षा कोडिंग और कंप्यूटेशनल चिंतन, फिटनेस जैसे क्षेत्रों में कौशल विकसित कर समृद्ध भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए भारतीय युवा सच्चे अर्थों में वैश्विक नागरिक का दायित्व निभा सकेंगे। देश के युवाओं ने फ्लिपकार्ट, ओयो, पेटीएम, स्विग्गी, बिग बास्केट, लूम सोलर, प्रैक्टो पिपर फ्राई, इंडिया मार्ट आदि बड़ी कंपनियां स्थापित की हैं। अनेक उदाहरण युवाओं के सामने है। युवाओं के सामने ऐसा विकल्प रख कर ही उन्हें सोचने की क्षमता प्रदान की जा सकती है ।

कोविड काल में एमएसएमई

सुक्ष्म, लघु मैन्युफैक्चरिंग उद्यम रोजगार सृजन के अवसरों के लिए जाने जाते हैं। कोविड–19 संकट से भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रमुख योगदानकर्ता –एमएसएमई अर्थात सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुवे हैं । सरकार ने भारतीय उद्योग की रीढ़ सूक्ष्म, लघु एवं मघ्यम उद्यमों के लिए नीतियों में साहसिक बदलाव किया। इसमें न केवल सिर्फ टर्नओवर के हिसाब से इनका वर्गीकरण बदल गया, बल्कि 200 करोड़ तक के किसी भी टेंडर में इनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ग्लोबल कंपनियों को इस दायरे से बाहर कर दिया गया है। जिससे अच्छी रिकवरी रेट के साथ ही देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।

आत्मनिर्भरता में स्टार्टअप की भूमिका

स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की अहम् पहल है जिसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप्स और नये विचारों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है

जिससे देश का आर्थिक विकास हो एवं बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न हों। 'स्टार्टअप इंडिया स्टैंडअप इंडिया' देश के युवाओं के लिये एक प्रभावी योजना है। ये पहल युवाओं को उद्योगपति और उद्यमी बनने का अवसर प्रदान करने के लिये शुरू की गयी है। भारत सरकार ने वर्ष 2022 से 16 जनवरी को 'राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस' के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय युवाओं को उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित करेगी। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस की घोषणा से देश की जीडीपी वृद्धि में स्टार्टअप की भूमिका को मान्यता मिली है, और इससे युवा उद्यमिता को करियर विकल्प के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। यह एक प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों के नए नए स्टार्टअप और नवाचारों को प्रोत्साहित करने का सरकार का संकल्प भी है। वर्तमान में देश में 60,000 से अधिक स्टार्टअप इकाइयां हैं, जिनमें से 42 यूनिकॉर्न हैं, अर्थात इनकी वित्तीय पूंजी एक अरब डॉलर से अधिक मूल्यांकित की जा चुकी हैं। सरकार ने भविष्य की प्रौद्योगिकियों के लिए स्टार्टअप में अनुसंधान और विकास में निवेश को बढ़ावा देना अपनी प्राथमिकता में रखा हुवा है। इसीलिए देश भर में उद्यमिता के विस्तार और गहराई को प्रदर्शित करने के लिए सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया नवोन्मेषण सप्ताह (10–16 जनवरी) मनाया है। स्टार्टअप की दुनिया में वर्ष 2021 को 'यूनिकॉर्न के वर्ष' के रूप में मान्यता भी दी गई हैं। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस का आरंभिक लक्ष्य उद्यमशीलता एवं नवोन्मेषण को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख स्टार्टअप्स, उद्यमियों, निवेशकों, इनक्यूबेटरों, वित्त पोषण करने वाले निकायों, बैंकों, नीति निर्माताओं आदि को एक मंच पर लाना है।

इन्नोवेशन – स्टार्टअप परितंत्र

स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत एक वैश्विक इन्नोवेशन हब के रूप में उभर रहा है। विश्व की एक तिहाई स्टार्टअप परितंत्र का देश होने का गौरव हासिल हुवा है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने अभी तक 61,000 से अधिक स्टार्टअप्स को मान्यता दी है, जो 55 उद्योगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। देश के प्रत्येक राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश में कम से कम एक स्टार्टअप के साथ ये 633 जिलों में फैले हुए हैं, जिन्होंने वर्ष 2016 से लेकर अब तक 6 लाख से अधिक रोजगारों का सृजन किया है। देश में चल रहे इनोवेशन कैंपेन ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में सुधार करने में मदद की है। 2015 में भारत इस रैंकिंग में 81वें नंबर पर था, जो वर्तमान इनोवेशन इंडेक्स में 46वें स्थान पर है। यह बड़ी उपलब्धि है। भारत में अकेले 2021 में 46 यूनिकॉर्न कंपनियां(1 अरब डॉलर से अधिक वैल्यूएशन वाली कंपनियां) सामने आई हैं, जिसने 2021 में 42 अरब डॉलर जुटाए हैं। हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार, भारत 2021 में अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में उभरा है। प्रतिभाशाली लोग स्टार्टअप्स के साथ काम करने के लिए भारत वापस आ रहे हैं, जिससे ब्रेन–ड्रेन प्रक्रिया को उलट दिया है। निकट भविष्य में न केवल यूनिकॉर्न बल्कि डेकाकॉर्न (10 अरब और उससे अधिक के मूल्यांकन वाली कंपनियां) की आवश्यकता है जो 21वीं सदी की समस्याओं को हल कर सकें।

स्वदेशी अर्थनीति के माध्यम से ही स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। सामर्थ्य, उद्यमशीलता, वैज्ञानिक उन्नति और कौशल के आधार पर आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर बढ़ना ही होगा। आत्मनिर्भरता सर्व समावेशी विकास से संबंधित है। आत्मनिर्भर भारत संकल्पना का उद्देश्य देश के नागरिको को सभी प्रकार से सबल, सक्षम एवं सफल बनाना है। आत्मनिर्भर व्यवस्था से गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं का उत्पादन एवं सेवाओं का सृजन होता है और देश के साथ ही संपूर्ण विश्व को इसके उपयोग का अवसर मिलता है। कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न संकट में आत्मनिर्भरता की संकल्पना को प्रतिष्ठित करने का अवसर मिला है। भारत के जनसांख्यिकी लाभांश दर्शा रहा है कि मांग और ग्राहक आधार बहुत बड़ा है । एक बेहतर नेटवर्क और बेहतर दूरसंचार नीति स्टार्टअप्स के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी। सरकार की यह आत्मनिर्भरता की पहल देश के उत्पादों के साथ वैश्विक बाजारों में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के योगदान की एक उत्कृष्ट स्वीकृति है, जिससे लाखों लोगों का जीवन प्रभावित होता है। नवाचार, उद्यमशीलता और स्टार्ट–अप्स का पारितंत्र भारत को आत्मनिर्भरता के मार्ग पर अग्रसर करेगी ।▪

दिसंबर, 2021 में सकल जीएसटी राजस्व संग्रह 1,29,780 करोड़ रुपये रहा

दिसंबर, 2021 के महीने के लिए राजस्व पिछले साल के इसी महीने में जीएसटी राजस्व से 13% अधिक और दिसंबर, 2019 में जीएसटी राजस्व से 26% अधिक है

केन्द्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा एक जनवरी को जारी विज्ञप्ति के अनुसार दिसंबर, 2021 में सकल जीएसटी राजस्व संग्रह 1,29,780 करोड़ रुपये रहा, जिसमें सीजीएसटी 22,578 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 28,658 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 69,155 करोड़ रुपये (वस्तुओं के आयात पर संग्रह किए गए 37,527 करोड़ रुपये सहित) और उपकर (सेस) 9,389 करोड़ रुपये (वस्तुओं के आयात पर संग्रह किए गए 614 करोड़ रुपये सहित) शामिल हैं।

केंद्र सरकार ने नियमित निपटान के रूप में सीजीएसटी के लिए 25,568 करोड़ रुपये और आईजीएसटी से एसजीएसटी के लिए 21,102 करोड़ रुपये का निपटान किया है। दिसंबर, 2021 में नियमित निपटान के बाद केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा अर्जित कुल राजस्व सीजीएसटी के लिए 48,146 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के लिए 49,760 करोड़ रुपये है।

दिसंबर, 2021 के महीने के लिए राजस्व पिछले साल के इसी महीने में जीएसटी राजस्व से 13% अधिक और दिसंबर, 2019 में जीएसटी राजस्व से 26% अधिक है। महीने के दौरान माल के आयात से राजस्व 36% अधिक था और राजस्व घरेलू लेनदेन से (सेवाओं के आयात सहित) पिछले वर्ष के इसी महीने के दौरान इन स्रोतों से प्राप्त राजस्व से 5% अधिक है।

अक्टूबर, 2021 (7.4 करोड़) के महीने की तुलना में नवंबर, 2021 (6.1 करोड़) के दौरान ई-वे बिलों की संख्या में 17% की कमी के बावजूद महीने में जीएसटी संग्रह 1.30 लाख करोड़ रुपये के करीब है। केंद्रीय और राज्य दोनों कर प्राधिकरणों द्वारा बेहतर कर अनुपालन और बेहतर कर प्रशासन के कारण यह संभव हुआ।

चालू वर्ष की तीसरी तिमाही के लिए औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रह 1.30 लाख करोड़ रुपये रहा है, जबकि पहली और दूसरी तिमाही में औसत मासिक संग्रह क्रमशः 1.10 लाख करोड़ रुपये और 1.15 लाख करोड़ रुपये था। आर्थिक सुधार के साथ चोरी-रोधी गतिविधियों, विशेष रूप से नकली बिलर्स के खिलाफ कार्रवाई, जीएसटी को बढ़ाने में योगदान दे रही है। राजस्व में सुधार शुल्क ढांचे को ठीक करने के लिए परिषद् द्वारा उठाए गए विभिन्न युक्तिकरण उपायों के कारण भी हुआ है। उम्मीद है कि राजस्व में सकारात्मक रुझान अंतिम तिमाही में भी जारी रहेगा। ■

3.68 करोड़ लोगों ने 'अटल पेंशन योजना' में कराया नाम दर्ज

अटल पेंशन योजना (एपीवाई) में अभी तक 3.68 करोड़ लोगों ने अपना नाम दर्ज कराया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा पांच जनवरी को जारी विज्ञप्ति के अनुसार इस वित्त वर्ष में 65 लाख से अधिक लोगों ने इसमें नामांकन किया है, जो योजना के शुरू होने से इस अवधि में अब तक का सबसे अधिक नामांकन है। नामांकन के अलावा पुरुष से महिला सदस्यता अनुपात 56:44 में सुधार हो रहा है और प्रबंधन के तहत संपत्ति (एयूएम) लगभग 20,000 करोड़ रुपये है।

9 मई, 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने असंगठित क्षेत्रों में नागरिकों को वृद्धावस्था आय सुरक्षा देने के उद्देश्य से भारत सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना एपीवाई की शुरुआत की थी।

दरअसल, समाज के सबसे कमजोर वर्गों को पेंशन के दायरे में लाने का यह अद्भुत काम सार्वजनिक और निजी बैंकों के अथक प्रयासों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भुगतान बैंक, लघु वित्त बैंक, सहकारी बैंक, डाक विभाग और राज्य स्तरीय बैंकर समितियों द्वारा दिए गए समर्थन से संभव हो सका है।

गौरतलब है कि 18 से 40 वर्ष की आयु के किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा एपीवाई की सदस्यता ली जा सकती है, जिसके पास बैंक खाता है। इसके तीन प्रमुख लाभ हैं। सबसे पहला इसमें 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 1000 रुपये से 5000 रुपये तक की न्यूनतम गारंटी पेंशन प्रदान की जाती है। दूसरा यह है कि अभिदाता (बीमित व्यक्ति) की मृत्यु होने पर जीवन-साथी को जीवन भर के लिए पेंशन राशि की गारंटी दी जाती है और अंत में अभिदाता और पति या पत्नी दोनों की मृत्यु की स्थिति में पूरी पेंशन राशि का भुगतान नॉमिनी को किया जाता है। ■

देश में 15 से 18 वर्ष के आयुवर्ग के बच्चों का कोविड-19 रोधी टीकाकरण शुरू

देश में 15 से 18 वर्ष के आयुवर्ग के बच्चों को तीन जनवरी से कोविड–19 रोधी टीकों की खुराक दी जानी शुरू कर दी गई। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 27 दिसंबर को दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा था कि इस आयुवर्ग के बच्चों को कोविड–19 रोधी 'कोवैक्सिन' टीके की खुराक दी जाएगी।

भारत के औषधि महानियंत्रक ने 24 दिसंबर को कुछ शर्तों के साथ 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए स्वदेशी रूप से विकसित भारत बायोटेक के कोविड–19 रोधी 'कोवैक्सिन' टीके के आपात स्थिति में उपयोग की स्वीकृति दे दी थी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किशोरों को टीका लगवाने पर बधाई दी। श्री मोदी ने इनके माता–पिता को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि आज हमने कोविड–19 के खिलाफ अपने किशोरों को सुरक्षित करने के लिये एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। टीका लगवाने वाले 15 से 18 वर्ष आयुवर्ग के मैं अपने सभी किशोर मित्रों को बधाई देता हूं। मैं उनके माता–पिता को भी बधाई देता हूं। मैं अन्य किशोरों से भी आग्रह करता हूं कि वे आने वाले दिनों में टीके लगवा लें।

इस संदर्भ में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण के अंतर्गत आज से देशभर में 15 से 18 आयुवर्ग के बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान की षुरुआत हो गयी है। हमारे यंग इंडिया को कोरोना का सुरक्षा कवच देने हेतु मैं मोदी जी का धन्यवाद करता हूं।

12,031 करोड़ रुपये की हरित ऊर्जा कॉरिडोर चरण-II को मिली मंजूरी

इस योजना से सात राज्यों— गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में ग्रिड एकीकरण और लगभग 20 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा की बिजली निकासी परियोजनाओं को मदद मिलेगी

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में छह जनवरी को अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएनएसटीएस) के लिये हरित ऊर्जा कॉरिडोर (जीईसी) चरण-II की योजना को मंजूरी दे दी। इसके तहत लगभग 10,750 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइन तथा सब-स्टेशनों की लगभग 27,500 मेगा वोल्ट-एम्पियर (एमवीए) ट्रांसफार्मर क्षमता को अतिरिक्त रूप से जोड़े जाने को मंजूरी दी गई। इस योजना से सात राज्यों— गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में ग्रिड एकीकरण और लगभग 20 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा की बिजली निकासी परियोजनाओं को मदद मिलेगी।

इस योजना को कुल 12,031.33 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) परियोजना के 33 प्रतिशत के बराबर यानी 3970.34 करोड़ रुपये होगी। पारेषण प्रणाली को वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की पांच वर्ष की अवधि के दौरान तैयार किया जायेगा। केंद्रीय वित्तीय सहायता से राज्यांतरिक पारेषण शुल्कों का समायोजन करने में मदद मिलेगी और इस तरह बिजली की कीमत को कम रखा जा सकेगा। लिहाजा, बिजली के अंतिम उपयोगकर्ता– देश के नागरिकों को ही सरकारी सहयोग से फायदा पहुंचेगा।

इस योजना से 2030 तक 450 गीगावॉट स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यह योजना देश में दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा में योगदान करेगी तथा कार्बन उत्सर्जन को कम करके पारिस्थितिक रूप से सतत वृद्धि को बढ़ावा देगी। इससे बिजली और अन्य सम्बंधित सेक्टरों में कुशल और अकुशल, दोनों तरह के कामगारों के लिये बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे।

यह योजना जीईसी-चरण-I के अतिरिक्त है, जो ग्रिड एकीकरण तथा लगभग 24 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा निकासी के संदर्भ में आंध्रप्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु में पहले से चल रही है। उम्मीद है कि 2022 तक यह पूरी हो जायेगी। जिन सब-स्टेशनों के पास 4056.67 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) सहित 10,141.68 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली पारेषण परियोजनाएं हैं, यह योजना उन सब-स्टेशनों में 9,700 सर्किट किलोमीटर अतिरिक्त पारेषण लाइनों और उनमें 22,600 एमवीए की अतिरिक्त क्षमता जोड़ने के लिये है। ■

अक्टूबर, 2021 में खनिज पदार्थों का उत्पादन 20.4 प्रतिशत बढ़ा

जिन महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों के उत्पादन में अक्टूबर, 2020 की तुलना में अक्टूबर, 2021 में सकारात्मक वृद्धि देखने को मिली, उनमें सोना (55.7%), लिग्नाइट (49.7%), मैग्नेसाइट (33.1%), क्रोमाइट (30%), प्राकृतिक गैस (यू) (25.8%) और कोयला (14.5%) शामिल हैं

केन्द्रीय खान मंत्रालय द्वारा 27 दिसंबर को जारी विज्ञप्ति के अनुसार अक्टूबर, 2021 (आधारः 2011-12=100) महीने के लिए खनन और उत्खनन क्षेत्र के खनिज पदार्थों के उत्पादन का सूचकांक 109.7 पर रहा, जो पिछले वर्ष के स्तर की तुलना में 20.4 % अधिक था। अप्रैल-अक्टूबर 2020-21 की अवधि के लिए संचयी वृद्धि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 11.4 प्रतिशत बढ़ी है।

अक्टूबर, 2021 में महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन स्तर थाः कोयला 639 लाख टन, लिग्नाइट 37 लाख टन, पेट्रोलियम (कच्चा) 25 लाख टन, बॉक्साइट 1792 हजार टन, क्रोमाइट 130 हजार टन, सोना 109 किलो, लौह अयस्क 190 लाख टन, सीसा सांद्र 33 हजार टन, मैंगनीज अयस्क 202 हजार टन, जस्ता सांद्र 137 हजार टन, चूना पत्थर 319 लाख टन, फास्फोराइट 127 हजार टन, मैग्नेसाइट 10 हजार टन और हीरा 24 कैरेट।

जिन महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों के उत्पादन में अक्टूबर, 2020 की तुलना में अक्टूबर, 2021 में सकारात्मक वृद्धि देखने को मिली, उनमें सोना (55.7%), लिग्नाइट (49.7%), मैग्नेसाइट (33.1%), क्रोमाइट (30%), प्राकृतिक गैस (यू) (25.8%) और कोयला (14.5%) शामिल हैं। ■

वैचारिकी

सिद्धांत और नीतियां

पं. दीनदयाल उपाध्याय

जनवरी, 1965 में विजयवाड़ा में जनसंघ के बारहवें सार्वदेशिक अधिवेशन में स्वीकृत दस्तावेज

लोक शिक्षा

शालेय अध्ययन के अतिरिक्त लोक-संस्कार, स्वाध्याय, लोकमत परिष्कार भी शिक्षा के साधन हैं। इस दृष्टि से रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, संगीत तथा पत्र-पत्रिकाओं, पुस्तकालयों, क्लबों आदि का भरपूर उपयोग किया जा सकता है। इनकी योग्य व्यवस्था की ओर राज्य को ध्यान देना चाहिए।

रेडियो और टेलीविजन को सरकारी विभाग के स्थान पर एक स्वायत्त निगम के रूप में चलाना चाहिए।

चित्रपट लोक-शिक्षा का एक अत्यंत प्रभावी साधन है। अभिव्यक्ति के इस माध्यम का विकास करना चाहिए। किंतु शासन को यह ध्यान रखना चाहिए कि चित्रपट लोकमत-परिष्कार तथा सुरुचि पैदा करने के साधन बनने के स्थान पर लोगों की रुचि बिगाड़नेवाले न बनें।

विदेश नीति

राष्ट्र के उदात्त हितों का संरक्षण ही किसी देश की विदेश नीति का प्रमुख आधार है। भारतीय राष्ट्र की प्रकृति और परंपरा साम्राज्यवादी विस्तारवाद के प्रतिकूल मानव की समानता और आत्मीयता के आधार पर विश्व-एकता की रही है। विश्व शांति और विश्व की एकता भारत की राष्ट्रीय मनीषा है। जब तक विश्व में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद कायम है, जब तक रंग, धर्म और विचारों के भेद के आधार पर दूसरों को हेय समझने की प्रवृत्ति मौजूद है, जब तक राष्ट्रों के बीच भारी आर्थिक विषमताएं और उनके कारण शोषण विद्यमान है और जब तक दुनिया में युद्ध और शांति की ठेकेदारी दो-चार बड़े राष्ट्रों के पास है, तब तक विश्व में तनाव कम नहीं होंगे तथा हम सदैव ही एक कगार पर खड़े रहेंगे। आवश्यकता है कि पराधीन राष्ट्र स्वतंत्र हों, मानवाधिकारों की सर्वत्र मान्यता हो, विश्व को समान स्तर पर लाया जाए, विभिन्न राष्ट्रों के बीच सहयोग का क्षेत्र विस्तृत हो तथा अंतरराष्ट्रीय संस्था के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ अधिक सबल, प्रातिनिधिक एवं न्याययुक्त आधार पर विकसित हो। ऐसे अंतरराष्ट्रीय मोरचों का विकास भी आवश्यक है, जहां राज्यों के शासकीय प्रतिनिधियों के स्थान पर जन प्रतिनिधि एकत्र होकर मोरचों में राष्ट्र-राष्ट्र के बीच विद्यमान खाई को पाट सकें। भारतीय दर्शन विश्व की विविधता को स्वीकार करता है। अतः भारतीय जनसंघ प्रत्येक राष्ट्र के मूलभूत अधिकार को मानता है कि वह अपनी जीवन पद्धति का स्वयं अपनी इच्छानुसार निर्माण करे तथा इस विचार का विरोध करता है कि सब एक ही सांचे में ढल जाएं।

विदेशों से संबंधों का आधार

विश्व के विभिन्न देशों के साथ भारत के संबंधों का निर्धारण किसी एक मोटे नियम के अधीन नहीं हो सकता। सबकी मित्रता और सद्भावना के इच्छुक भारत को मूलतः सम-सहयोग की नीति लेकर चलना होगा। बिना शक्ति और पौरुष के शांति की आकांक्षा दुर्जनों को बढ़ावा देनेवाली और अंत में शांति के लिए घातक होती है। भारत को अपनी विदेश नीति तेजस्वी बनानी होगी। अंतिम लक्ष्यों को सामने रखते हुए उसे परिस्थिति के अनुसार विभिन्न राष्ट्रों के साथ शत्रु-मित्र भावों का निर्धारण यथार्थवादी आधार पर करना होगा। किसी भी एक अपरिवर्तनीय नीति से बंधे रहना अनीतिमत्तापूर्ण होगा। विश्व को दो शक्ति गुटों के बीच बंटा मानकर किसी के साथ लगाव या तटस्थता का विचार बीते दिनों की बात तथा अयथार्थपूर्ण है।

आक्रांत भू-भाग की मुक्ति

कम्युनिस्ट चीन और पाकिस्तान दोनों ही भारत के स्वाभाविक शत्रु हैं। दोनों ने भारत की सीमाओं पर अतिक्रमण करके देश के बड़े भू-भाग पर बलात् अधिकार कर रखा है। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का अहित ही दोनों की नीतियों का प्रमुख लक्ष्य है। भारत का प्रयत्न होना चाहिए कि वह अपने खोए हुए भागों को वापस ले तथा दोनों की आक्रामक प्रवृत्तियों को प्रतिबंधित करे।

पाकिस्तान के प्रति दृढ़ता

पाकिस्तान की जनता मूलतः भारतीय राष्ट्र का अंग है। वह

पृथकतावादी राजनीतिक शक्तियों का शिकार बनकर अलग हुई है। पाकिस्तान की निर्मिति के बाद से वह बराबर पीड़ित है। जिस स्वर्ग की उसे आशा दिखाई गई थी, वह मृग मरीचिका सिद्ध हुई। पाकिस्तान के शासक भारत-विरोधी भावनाएं भड़काकर अपना आसन स्थिर करने की नीति लेकर चल रहे हैं। भारत द्वारा अपनाई गई तुष्टीकरण की नीति ही उनका सबसे बड़ा बल है। भारत यदि दृढता की नीति अपनाए तो पाकिस्तानी विरोध का बुलबुला अधिक दिनों तक नहीं टिक सकता।

कम्युनिस्ट चीन का संकट

कम्युनिस्ट चीन भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए ही नहीं, अपितु संपूर्ण विश्व के लिए एक संकट बना हुआ है। सभी शांतिवादी एवं सह-अस्तित्व के पुजारी देशों के सहयोग से कम्युनिस्ट चीन की विस्तारवादी एवं युद्धलोलुप प्रवृत्ति का विरोध करना होगा। तिब्बत, सिंक्यांग, मंचूरिया और मंगोलिया की स्वतंत्रता फारमोसा सरकार की मान्यता तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों की चीन प्रभाव से मुक्ति इस दृष्टि से आवश्यक है।

सांस्कृतिक संबंधों का पुनरुज्जीवन

दक्षिण-पूर्व एशिया तथा अन्य देशों के साथ भारत के ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। इन संबंधों को पुनरुज्जीवित कर सुदृढ़ करने की दिशा में कदम उठाने चाहिए।

भारतीय प्रवासी

विश्व के अनेक देशों में भारतीय प्रवासी विभिन्न कारणों से जाकर बसे हैं। उन देशों के विकास में उनका महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। इन देशों की स्वतंत्रता के बाद कहीं-कहीं उनके साथ विभेदपूर्ण व्यवहार हुआ है, जिससे वे भविष्य के प्रति आशंकित हैं। भारत का यह दायित्व है कि उन प्रवासियों को समान अधिकार प्राप्त हों, जिससे वे उन देशों की प्रगति में अपना समुचित योगदान कर सकें।

अफ्रीकी देशों से संबंध

अफ्रीकी देशों की स्वतंत्रता सदैव से भारत की रुचि और समर्थन का विषय रही है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का उनके साथ घनिष्ठ संबंध रहा है। इन स्वतंत्र देशों के साथ सहयोग और मित्रता के संबंध सुदृढ़ करने की नीति बढ़नी चाहिए।

आर्थिक नीति

भारत की वर्तमान अर्थव्यवस्था विशृंखलित है। वह न तो व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है और न समाज के सुरक्षा सामर्थ्य की गारंटी दे सकती है। उसका पुनर्गठन करना होगा।

स्वदेशी का मंत्र

उत्पादन वृद्धि के बिना देश की समृद्धि संभव नहीं। किंतु समृद्धि की साधना और फल में सभी लोग साझीदार हों, इस हेतु हमें समतर वितरण का भी ध्यान रखना होगा। वितरण को सुधारे बिना न तो आज का निर्धन धनवान् होने का अनुभव कर सकेगा और न उत्पादन वृद्धि के लिए आवश्यक क्षमता और संकल्प जुटा सकेगा। पैदा माल की खपत के लिए बाजार का विस्तार जनसामान्य की क्रयशक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि से ही संभव है।

अर्थव्यवस्था को गतिमान बनाने तथा उत्पादन वृद्धि के लिए पूंजी-निर्माण आवश्यक है। पूंजी के लिए बचत और साहस चाहिए। भारत में अधिकांश लोगों का जीवन स्तर इतना नीचा है कि उपभोग को टालकर बचत की गुंजाइश ही नहीं। साथ ही, परानुकरण से उत्पन्न दिखावा करने की प्रवृत्ति तथा जीवन-मूल्यों में परिवर्तन के कारण जीवन स्तर की धारणा में भी अंतर आया है। हमारी उपभोग-प्रवणता, गुण और मात्रा दोनों में, बड़ी तेजी से बदल रही है। फलतः पुराने धंधों में बेकारी और विपूंजीकरण तथा नए में अभाव की स्थिति पैदा हो गई है। आधुनिकीकरण के नाम पर पाश्चात्यीकरण तेजी से आ रहा है। सामाजिक क्षेत्र के अतिरिक्त आर्थिक क्षेत्र में भी इससे अनेक समस्याएं तथा अवांछनीय प्रवृत्तियां जन्म ले रही हैं। आवश्यकता इस बात की है कि स्वदेशी के मंत्र का पुनरुच्चार किया जाए। इससे आवश्यक संयम एवं स्वावलंबन का भाव जागेगा तथा अनावश्यक रूप से विदेशी पूंजी पर निर्भरता के व्यामोह तथा उसके प्रभाव से बचेंगे।

> **उत्पादन वृद्धि के बिना देश की समृद्धि संभव नहीं। किंतु समृद्धि की साधना और फल में सभी लोग साझीदार हों, इस हेतु हमें समतर वितरण का भी ध्यान रखना होगा**

नियोजन

राष्ट्र के साधनों को न्यूनतम काल में अधिकतम लाभ के लिए प्रयुक्त करने की दृष्टि से आर्थिक नियोजन की आवश्यकता है। किंतु योजना साधन है, साध्य नहीं। उसका निर्माण राज्य की स्थायी निष्ठाओं की मर्यादाओं के अंतर्गत ही करना होगा। भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता, लोकतंत्र तथा भारतीय संस्कृति के शाश्वत मूल्य वे निष्ठाएं हैं, जिनके प्रतिकूल अर्थोत्पादन की कोई योजना स्वीकार नहीं की जा सकती। वास्तव में ये मर्यादाएं नियोजकों के मार्ग में रुकावट नहीं, बल्कि उनके संबल हैं। यदि उनका सही-सही उपयोग किया जाए तो उनसे राष्ट्र के सामूहिक प्रयत्नों को भारी बल मिल सकता है। कल की समृद्धि के लिए आज के कष्टों की प्रेरणा केवल आर्थिक उद्देश्यों से नहीं मिल सकती। जन-मन में योजना की सिद्धि की आकांक्षा जाग्रत् करने के लिए उसे आदर्शवादी बनना होगा, किंतु उसके लक्ष्य जनता के संभव सामर्थ्य की कल्पना कर यथार्थ की ठोस भूमि पर ही निर्धारित करने चाहिए। ■

बढ़ता कारवाँ...

पत्रिका पंजीकरण – RNI-51899/91 डाक पंजीकरण – SSP/LW/NP-117-2021-23
जनवरी द्वितीय सुराज अंक 2022 – प्रेषित डाकघर – R.M.S. चारबाग, लखनऊ – प्रेषण तिथि : 26–29 (द्वितीय पाक्षिक)

भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्रक तथा प्रकाशक प्रो. श्यामनन्दन सिंह द्वारा नूतन ऑफसेट मुद्रण केन्द्र, संस्कृति भवन, राजेन्द्र नगर, लखनऊ से मुद्रित व भाजपा कार्यालय, 7, विधानसभा मार्ग, लखनऊ से प्रकाशित। सम्पादक : अरूण कान्त त्रिपाठी